सैन्य सन्देश

Sainya Sandesh

युगाब्द 5127 | आश्विन-कार्तिक 2082 | अक्टूबर, 25

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष

विशेषांक

अखिल भारतीय पूर्व-सैनिक सेवा परिषद् का मुखपत्र

गोरक्ष प्रांत (उ.प्र.)

असम

गुजरात

गुवाहाटी (असम)

काशी प्रांत (उ.प्र.)

राजस्थान

लखनऊ (उ.प्र.)

कुशीनगर (उ.प्र.)

रीवा (म.प्र.)

मेरठ प्रांत (उ.प्र.)

RNI Reg No.UPBIL/2002/9228

27. December 2023 Postal Reg. SSP/LW/NewsPaper-01-2024-2026
Despatched from- Lko RMS Non TD.
Dates of Despatch- 5,22 & 28

एबीपीएसएसपी (दिल्ली)

हरदोई (उ.प्र.)

अवध प्रांत (उ.प्र.)

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद

के सदस्य बनें और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें

मो. : 8317082620, 8004402890
Website: www.sainyasandesh.co.in
E-mail : sainyasandesh@gmail.com, info@sainyasandesh.co.in

सेवा में

अ.भा. पूर्व सैनिक सेवा परिषद के लिए अतिथि मुद्रक एवं प्रकाशक कर्नल लक्ष्मीकांत तिवारी ने हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा, हजरतगंज, लखनऊ से मुद्रित कराकर, 3 नीवन मार्केट, बी.एन.रोड, कैसरबाग, लखनऊ से प्रकाशित किया।

सैन्य-सन्देश (मासिक)

राष्ट्रहित, समाजहित, सैनिक-हित को समर्पित पत्रिका

अखिल भारतीय पूर्व-सैनिक सेवा परिषद का मुख-पत्र

वर्ष–26 | आश्विन–कार्तिक 2082 | अक्टूबर, 2025

संरक्षक मण्डल

ले.ज.वी.के.चतुर्वेदी PVSM,AVSM,SM

ए.वी.एम. एच.पी. सिंह, VrC, VSM

प्रबन्धक मण्डल

ब्रिगेडियर डी एस त्रिपाठी

ब्रिगेडियर गोविन्दजी मिश्र VSM,PPM

सम्पादकीय सलाहकार

ले.जन. दुष्यन्त सिंह PVSM,AVSM

मुख्य सम्पादक

कर्नल लक्ष्मीकान्त तिवारी

सह-सम्पादक

सू.मे. जे.बी.एस. चौहान, राष्ट्रीय सह सचिव

कोषाध्यक्ष

श्री प्रमोद कुमार तिवारी, राष्ट्रीय सह सचिव

प्रबन्धन विपणन एवं प्रचार-प्रसार

ले. कर्नल वीरेन्द्र सिंह तोमर

सीपीओ घनश्याम प्रसाद केसरी

(सभी पद अवैतनिक)

मुद्रित :

हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा प्रा0 लि0

प्रस्तुति

हिन्दी अनुभाग

1. संपादक की कलम से राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष... 2
2. आरएसएस : राष्ट्र निर्माण की शताब्दी यात्रा 3–4
3. शोधार्थियों को प्रोत्साहन की कमी 5–6
4. विकसित भारत के अनुकूल बने पुलिस 7–8
5. दिखती है हिंसा की साजिश 9–10
6. किसानों के लिए वरदान है नया जीएसटी 11–12
7. भारत-रूस संबंध 13–14
8. एक-दूसरे की जरूरत बने भारत-ब्रिटेन 15–16
9. ट्रम्प टैरिफ, नीति और भारत की सूझबूझ 17–18
10. यथार्थ के युग प्रवर्तक लेखक 19–20

English Section

1.100 years of the RSS : The sprit remains... 21-22
2. Dealing with Sensitive Ladakh 23-24
3. Why an armed forces officer must be... 25-26
4. Beyond Active Service 27-28
5. 100 years of RSS and the three wars... 29-31
6. India's Economic Outlook 32
7. 4 key obstancles to India Joining... 33-34
8. गतिविधियां 35-36

सम्पादकीय कार्यालय : 3, नवीन मार्केट, बी.एन. रोड, कैसरबाग, लखनऊ–226001

मो. : 8004402890, 8317082620, 9651217002

Website: www.sainyasandesh.co.in

E-mail : sainyasandesh@gmail.com

The Publishers and Authors reserve the rights in regard to the contents of 'Sainya Sandesh'. The images and certain content used herein are from public domain, belongs to their respective owners and the same is being used herein for awareness and educational purposes only. The Magazine is non commercial, non profitable and intended to create awareness amongst soldiers community.

राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष
तपस्या, संकल्प और गौरवशाली यात्रा

आज, जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो हृदय गर्व, भावना और कृतज्ञता से भर जाता है। यह केवल किसी संगठन की शताब्दी नहीं है, बल्कि यह एक विचार की विजय का उत्सव है, एक अनवरत साधना का परिणाम है, और उन असंख्य गुमनाम नायकों के त्याग और तपस्या को नमन करने का अवसर है जिन्होंने 'राष्ट्र सर्वोपरि' के मंत्र को अपने जीवन का आधार बनाया। आज से एक सदी पूर्व, जब भारत पराधीनता की बेड़ियों और आत्म–विस्मृति के अंधकार में डूबा हुआ था, तब परम पूजनीय डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जी ने एक सपना देखा था। उन्होंने एक ऐसे शक्तिशाली, संगठित और चरित्रवान हिंदू समाज की कल्पना की जो भारत को उसके परम वैभव पर पुनर्स्थापित कर सके। नागपुर की भूमि पर लगाया गया वह छोटा–सा बीज आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है, जिसकी शाखाएं देश के कोने–कोने में फैली हैं और जिसकी जड़ें भारत की सनातन संस्कृति में गहराई तक समाई हुई हैं।

यह 100 वर्षों की यात्रा फूलों की सेज नहीं रही। यह एक मौन साधकों की गाथा है, जिन्होंने बिना किसी पद या प्रतिष्ठा की चाह के, अपने जीवन का प्रत्येक क्षण माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रभात की पहली किरण के साथ लगने वाली शाखा से लेकर राष्ट्र पर आई हर विपदा में सबसे आगे खड़े स्वयंसेवक तक, यह कहानी निःस्वार्थ सेवा और अटूट अनुशासन की है। चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, या कोई अन्य राष्ट्रीय आपदा, खाकी नेकर पहने स्वयंसेवक का अनुशासित और सेवाभावी स्वरूप करोड़ों भारतीयों के लिए आशा और विश्वास का प्रतीक बन गया है। संघ ने समाज के हर वर्ग को एक सूत्र में पिरोकर, जाति–पाति और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, एक सशक्त और समरस समाज की नींव रखी है। अनेकों झंझावातों, आलोचनाओं और विरोध के बावजूद संघ अपनी ध्येयनिष्ठा पर अडिग रहा, क्योंकि उसका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक ऐसी राष्ट्रभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करना रहा है जो हर भारतीय के दिल में जलती रहे।

आज, जब भारत विश्व पटल पर एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो इसके पीछे संघ द्वारा जगाई गई सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय स्वाभिमान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शताब्दी समारोह केवल अतीत का स्मरण नहीं, बल्कि भविष्य का संकल्प है। यह संकल्प है भारत को 'विश्व गुरु' के पद पर आसीन देखने का, यह संकल्प है प्रत्येक भारतीय के मन में अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों के प्रति अटूट श्रद्धा जगाने का।

हम उन सभी ज्ञात और अज्ञात स्वयंसेवकों को कोटि–कोटि नमन करते हैं, जिनके पसीने और बलिदान से यह संगठन सिंचित हुआ है। आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। हमें विश्वास है कि संघ की प्रेरणा से भारत अपनी नियति को अवश्य प्राप्त करेगा। संघ के शताब्दी वर्ष पर सभी स्वयंसेवकों और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएं!

कर्नल लक्ष्मी कान्त तिवारी
मुख्य संपादक

हमारा तिरंगा इसलिए नहीं फहरता है कि हवा चल रही होती है, बल्कि हमारा तिरंगा उस जवान की आखिरी सांस से फहरता है, जो हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए अपने प्राणों को यूंही न्योछावर कर देता है!

Our tricolor does not fly because the wind is moving, but our tricolor flutters with the last breath of the young man who sacrificed his life to protect our tricolor!

आरएसएस : राष्ट्र निर्माण की शताब्दी यात्रा

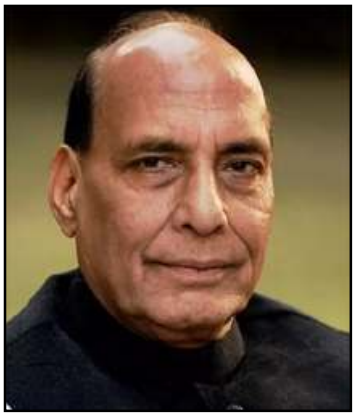

राजनाथ सिंह

27 सितंबर 1925 को जब डा. केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना की थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगामी सौ वर्षों में यह संगठन इतना विशाल और प्रभावशाली बन जाएगा। आरएसएस ने भारत की सामाजिक बुनियाद को मजबूत किया है, उसकी संप्रभुता की रक्षा की है, कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया है और भारतीय सभ्यता के मूल्यों को संजोए रखा है। आरएसएस निस्वार्थ सेवा का जीवंत प्रतीक है। आरएसएस के शताब्दी उत्सव के अवसर पर उसकी यात्रा को पुनः याद करना उचित भी है और आवश्यक भी। हाल में दिल्ली में सरसंघचालक मोहन भागवत ने संघ के समावेशी विचारों पर चर्चा करते हुए कहा था, 'धर्म व्यक्तिगत पसंद का विषय है। इसमें किसी तरह का प्रलोभन या जोर–जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए।' यह वक्तव्य संघ की मूल विचारधारा को प्रतिबिंबित करता है कि समाज में टकराव नहीं, सामंजस्य हो। आज भी संघ की दैनिक शाखाएं और स्वयंसेवकों के कार्यक्रम अनुशासन, आत्मबल और भारतीय संस्कृति पर गर्व करने की प्रेरणा देते हैं, जिससे श्रेष्ठ भारत के निर्माण का मार्ग सुगम होता है।

यह स्वाभाविक है कि संघ के अनुकरणीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से संघ को 'दुनिया का सबसे बड़ा गैर–सरकारी संगठन'। बताया। 1947 में जब भारत स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, तब विभाजन की त्रासदी से बहुत जनहानि हुई थी और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। ऐसी भीषण परिस्थिति में संघ के स्वयंसेवक अनुशासित, संगठित और निस्वार्थ सेवकों के रूप में सामने आए। उन्होंने विस्थापितों के पुनर्वास में अनन्य योगदान दिया। विभाजन से पहले भी दूसरे सरसंघचालक श्री गुरुजी (एमएस गोलवलकर) और संघ के कई वरिष्ठ नेताओं ने पंजाब के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और वहां लोगों को आत्मरक्षा और राहत कार्यों के लिए संगठित किया। उस दौरान संघ की भूमिका का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि तत्कालीन हालात से घबराए कांग्रेस नेताओं को भी अपने परिवारों और समुदाय की रक्षा के लिए संघ की मदद लेनी पड़ी। स्वयंसेवकों की सेवा के कारण ही द ट्रिब्यून अखबार ने आरएसएस को 'द स्वार्ड आर्म आफ पंजाब' कहा। संघ का समाज सेवा कार्य विभाजन के बाद भी अनवरत जारी रहा। 1984 में जब सिख विरोधी दंगे

भड़काए गए और हजारों सिखों की हत्या की गई, तब संघ स्वयंसेवक सिखों की रक्षा के लिए सबसे आगे थे। लेखक खुशवंत सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए लिखा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हिंदू–सिख एकता बनाए रखने में संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ के कार्यों को देखकर कहा जा सकता है कि कुछ लोगों द्वारा उस पर बहुसंख्यकवादी संगठन होने का आरोप बिल्कुल निराधार है। स्वतंत्रता के समय भी संघ ने अल्पसंख्यकों और उनके पूजास्थलों की रक्षा में मदद की। मार्च 1947 में जब मुस्लिम लीग द्वारा उकसाई गई भीड़ श्रीहरमंदिर साहिब की ओर बढ़ी, तो तलवारों–लाठियों से लैस संघ स्वयंसेवकों ने न केवल उसका सामना किया, बल्कि उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। तीन दिन बाद जब एक और सुनियोजित हमला श्रीहरमंदिर साहिब पर हुआ, तब भी स्वयंसेवकों ने मानव घेरा बनाकर गुरुद्वारे की रक्षा की और हमलावरों को खदेड़ा।

भारत के एकीकरण में संघ के योगदान से भी बहुत लोग अवगत नहीं हैं। जब पाकिस्तान समर्थित कबाइली हमलावरों ने जम्मू–कश्मीर पर आक्रमण किया, तो सरदार पटेल ने महाराजा हरि सिंह को विलय के लिए राजी करने हेतु गुरुजी की मदद मांगी। गुरुजी ने श्रीनगर जाकर हरि सिंह को तत्काल विलय के लिए मनाने का प्रयास किया। आरएसएस स्वयंसेवकों ने 1947–48 के युद्ध के दौरान सेना की सहायता की। साथ ही मीरपुर और मुजफ्फराबाद से भागे शरणार्थियों के लिए राहत कार्यों की व्यवस्था संभाली। 1954 में स्वयंसेवकों ने दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। केआर मलकानी की पुस्तक 'द आरएसएस स्टोरी' में इसका विवरण है। पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में कई स्वयंसेवकों ने प्राण न्योछावर किए।

आपातकाल के खिलाफ लाखों स्वयंसेवक संगठित होकर संविधान की रक्षा के लिए खड़े हुए। जनवरी 1976 में द इकोनमिस्ट ने लिखा था, इस आंदोलन की मुख्य ताकत जनसंघ और उससे जुड़ा संगठन आरएसएस है। उस समय जब लोगों और संस्थाओं को केवल झुकने को कहा जाता था, तो वे रेंगने को तैयार थे, तब संघ के असंख्य कार्यकर्ता तानाशाही के खिलाफ खड़े हुए और लोगों को एक लोकतांत्रिक विकल्प प्रदान करने के लिए काम किया। यह संघ के लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति संकल्प का प्रमाण है। वनवासी और हाशिए के समुदायों के उत्थान के लिए संघ कार्यों से भी यह बात पूर्णतया सिद्ध होती है। 1952 में स्थापित अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम देश का सबसे बड़ा आदिवासी कल्याण संगठन है।

आरएसएस को महात्मा गांधी जी के नाम पर अक्सर निशाना बनाया जाता है। महात्मा गांधी और आरएसएस के बीच कुछ वैचारिक मतभेद अवश्य रहे, लेकिन कभी वैमनस्य का भाव नहीं रहा। 1934 में गांधीजी ने वर्धा में आरएसएस के एक शिविर का दौरा किया, जहां उन्होंने संघ के अनुशासन, अस्पृश्यता के पूर्ण अभाव और उच्च सादगी की सराहना की। 16 सितंबर 1947 को गांधीजी ने दिल्ली में आरएसएस की एक सभा को संबोधित करते हुए संघ की सेवा एवं बलिदान की भावना की प्रशंसा की। 30 जनवरी, 1948 को गांधीजी की हत्या के बाद आरएसएस ने श्रद्धांजलि स्वरूप अपनी सभी शाखाएं 13 दिनों के लिए स्थगित कर दी थीं। ऐसा संघ के इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है। ये बातें एक–दूसरे के प्रति पारस्परिक सम्मान की गवाही देती हैं। आरएसएस ने विचारों की विविधता का हमेशा सम्मान किया है।

उपनिवेशवाद के दौरान हुए कुशासन और आजादी के बाद नीतिगत उपेक्षा के कारण पूर्वोत्तर भारत और वहां के लोग अलगाववाद और उग्रवाद से जूझते रहे, लेकिन आरएसएस ने 1946 में गुवाहाटी में पहली शाखा स्थापित की और तब से इस क्षेत्र को राष्ट्रीय धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब आरएसएस एक सदी की सफल यात्रा पूर्ण कर रहा है, तब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि राष्ट्र निर्माण में उसका योगदान अप्रतिम और अतुलनीय है। एक सदी बाद भी आरएसएस उसी भाव और समर्पण के साथ मानवता और देश की सेवा कर रहा है, जिसके साथ उसकी नींव रखी गई थी।

शोधार्थियों को प्रोत्साहन की कमी

प्रमोद भार्गव

पक्षियों के पंख अपने आप में संपूर्ण रूप में विकसित होते हैं, लेकिन हवा के बिना कोई भी पक्षी उड़ान नहीं भर सकता। यही स्थिति भारत में नवाचारी प्रयोगधर्मियों के साथ रही है। उनमें कल्पनाशील असीम क्षमताएं हैं, लेकिन कल्पनाओं को आकार देने के लिए प्रोत्साहन एवं वातावरण नहीं मिल पाता है। हालांकि 11 साल से सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने इस वातावरण के निर्माण में अकल्पनीय काम किया है, किंतु अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनर्गल फैसलों के चलते जरूरी हो गया है कि हम अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यनरत विद्यार्थियों की मौलिक सोच को शोध की दिशा में प्रेरित करें।

हाल में ट्रंप ने नासा और नेशनल साइंस फाउंडेशन जैसे शोध विकास संस्थानों के बजट में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कटौती कर दी है। एच–1बी वीजा की शुल्क में आवेदन के लिए एक लाख डॉलर यानी करीब 86 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान करने की शर्त लगा दी है। इस किस्म के वीजा के सबसे ज्यादा लाभार्थी वे दक्ष युवा भारतीय हैं, जो अमेरिका की आईटी कंपनियों में नौकरी के इच्छुक रहते हैं। ट्रंप भविष्य में ऐसे और कानूनी उपाय कर सकते हैं, जिनसे युवा उद्यमियों को अवसर मिलने में कमी आए। अतएव भारत को ऐसे कल्पनाशील शोधार्थियों को बढ़ावा देना जरूरी है, जिनमें नवाचारी प्रतिभा है। हालांकि नासा और नेशनल फाउंडेशन के बजट में कटौती के बाद यूरोप ने 'चूज यूरोप फॉर साइंस' थीम पर मई–2025 में बैठक कर दुनिया के शोधार्थियों के लिए अपने संस्थानों के द्वार खोल दिए हैं। फ्रांस और भारत ने बजट बढ़ा दिया है। चीन पूर्व से ही स्कूल स्तर पर छात्रों की मौलिक सोच एवं नूतन आविष्कार की संभावनाओं की पहचान कर छात्रों को अनुसंधान की दिशा में उन्मुक्त करने लग गया है। भारत ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना कर एक लाख करोड़ की धनराशि आवंटित की है जिससे शोध की सोच को आविष्कार के रूप में साकार किया जा सके।

दरअसल, हमारी अब तक दिक्कत यह रही है कि हम खुद न अपने आविष्कारकों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, और न ही उन्हें मान्यता देते हैं। इन प्रतिभाओं के साथ हमारा व्यवहार भी कमोबेश उपहासपूर्ण अभद्र रहता है। हालांकि अब निरंतर ऐसी प्रामाणिक सूचनाएं मीडिया में आ रही हैं, जिनसे निश्चित होता है कि प्राचीन भारत विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली था। संस्कृत ग्रंथों से यही ज्ञान अंग्रेजी,

फारसी और अरबी भाषाओं में अनूदित होकर पश्चिम पहुंचा और वहां के कल्पनाशील जिज्ञासुओं ने भारतीय सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप में ढाल कर अनेक आविष्कार व सिद्धांत गढ़ कर पेटेंट करा लिए। इनमें से ज्यादातर पश्चिमी वैज्ञानिक उच्च शिक्षित नहीं थे।

आविष्कारक शोधार्थी को जिज्ञासु एवं कल्पनाशील होना जरूरी है। कोई शोधार्थी कितना भी शिक्षित क्यों न हो, कल्पना बिना मौलिक या नूतन आविष्कार नहीं कर सकता। शिक्षा संस्थानों से विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसकी एक सीमा होती है। वह उतना ही बताती–सिखाती है, जितना हो चुका है। आविष्कार कल्पना की वह श्रृंखला है, जो हो चुके से आगे की अर्थात कुछ नितांत नूतन करने की जिज्ञासा को आधार–तल देती है। जब लब्धप्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की जीवन–गाथाओं को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि न तो वे उच्च शिक्षित थे, न ही वैज्ञानिक संस्थानों में काम करते थे और न ही उनके इर्द–गिर्द विज्ञान सम्मत परिवेश ही था। उन्हें प्रयोग करने के लिए प्रयोगशालाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। गोया, हम कह सकते हैं कि मौलिक प्रतिभा जिज्ञासु के अवचेतन में कहीं छिपी होती है। इसे पहचान कर गुणीजन या शिक्षक प्रोत्साहित कर कल्पना को पंख देने का माहौल दें तो भारत की ग्रामीण धरती से अनेक वैज्ञानिक–आविष्कारक निकल सकते हैं। इस दिशा में एक अच्छी पहल आईआईटी, मद्रास में श्सोच का पाठ पढ़ाने के पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ की है। यदि शिक्षक विद्यार्थी के अवचेतन में पैठ बनाए बैठे इस कल्पनाशील सोच को पहचानने में सफल होते हैं, तो इस पाठ्यक्रम की सार्थकता निकट भविष्य में सिद्ध हो जाएगी।

दुनिया में वैज्ञानिक और अभियंता पैदा करने की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान है। भारतीय शोधार्थियों का वैश्विक प्रतिशत 2 हैं, चर्चित शोध–पत्रों की प्रस्तुति में हमारा योगदान 2.4 प्रतिशत है। प्रसन्नता की बात है कि 29 प्रौद्योगिकी संपन्न देशों में भारत का स्थान पांचवा है। भारत ने उस प्रत्येक परिस्थिति को चुनौती और अवसर माना जो दूसरे देशों ने हमारे सामने पेश की। रूस ने भारत को अंतरिक्ष मिसाइल प्रक्षेपण से जुड़े क्रायोजनिक इंजन की तकनीक देने से मना कर दिया था । तब एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे देशज संसाधनों से विकसित किया और आज हम अंतरिक्ष में प्रमुख वैश्विक शक्ति हैं। इसी तरह 1987 में अमेरिका ने हमें सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। तब भौतिक शास्त्री विजय पांडुरंग भटकर ने इस स्थिति को चुनौती माना और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम स्वयं की मेधा से विकसित किया। अतएव ट्रंप के अवरोधों को हमें अवसर के रूप में देखने की जरूरत है।

सैन्य संदेश के सदस्य बनें

पत्रिका 'सैन्य संदेश' का सदस्य बनें। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के हर पदाधिकारी को पत्रिका का आजीवन सदस्य (Life Time Member) बनना अपेक्षित है। पत्रिका का वार्षिक शुल्क रू0 300/– और आजीवन सदस्यता शुल्क रू0 2500/– है। वार्षिक सदस्यों को एक वर्ष बाद पुनः सदस्यता नवीनीकरण अनिवार्य है जिसके लिये प्रति वर्ष रू0 300/– देय है। सदस्यता शुल्क आनलाइन पेयमेंट (Editor Sainya Sandesh A/c No. 0293000109102061 Punjab National Bank, IFS Code PUNB0029300) पर देय है। ऑनलाइन पेयमेंट का स्क्रीन शॉट सैन्य संदेश नेशनल whatsapp ग्रुप में या सम्पादक/सहसम्पादक/ कोषाध्यक्ष के फोन पर जो पत्रिका में सबसे पीछे के पृष्ठ पर अंकित है, भेजें। साथ में सब्सक्राइबर सदस्य का पोस्टल एड्रेस पिन कोड तथा मोबाइल नम्बर के साथ अवश्य भेजें।

विकसित भारत के अनुकूल बने पुलिस

प्रकाश सिंह

इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में पुलिस हिरासत में मौतों के कुछ मामलों की सुनवाई चल रही है। ये मामले मध्य प्रदेश और राजस्थान के हैं। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों का संज्ञान लिया, लेकिन और भी अच्छा होता कि वह पुलिस सुधार संबंधी 2006 के अपने आदेश के अनुपालन की वस्तुस्थिति भी देखे। 1996 में इन पंक्तियों के लेखक ने एक जनहित याचिका द्वारा पुलिस में सुधारों की मांग की। इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की बहस के बाद 22 सितंबर, 2006 में तीन संस्थागत परिवर्तन के निर्देश दिए थे। एक, हर राज्य में एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त करना हो । दो, एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बने और इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामले में अधिकार हो, एक कंप्लेंट अथारिटी की स्थापना की जाए, जो पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर शिकायतों की जांच करे एवं महानिदेशक के चयन के लिए ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए, जिससे केवल श्रेष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति उच्चतम पद पर हो सके और उनका कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का हो। तीन, इन्वेस्टिगेशन और कानून एवं व्यवस्था के कार्य को बड़े शहरों में अलग–अलग किया जाए। इस फैसले के बाद ऐसी आशा थी कि पुलिस विभाग को एक नई दिशा मिलेगी, पुलिस कर्मी देश के संविधान और कानून के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जनता के प्रति उनका व्यवहार संवेदनशील हो जाएगा, शांति व्यवस्था में सुधार होगा, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला दिए 20 साल हो गए। उसके निर्देशों के अनुपालन में कुछ राज्यों में आदेश निर्गत किए गए और कुछ में एक नया अधिनियम बना दिया गया, परंतु बारीकी से देखा जाए तो पता चलता है कि उक्त आदेश और अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। नतीजा यह है कि जमीनी स्तर पर हालात जस के तस हैं और कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।

वास्तव में राज्य सरकारों को लगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश सही ढंग से लागू किए गए तो पुलिस उनके नियंत्रण से बाहर चली जाएगी और वे उसका जैसा उपयोग–दुरुपयोग करती हैं, वैसा नहीं कर पाएंगी। फलस्वरूप नेताओं और नौकरशाहों ने मन बना लिया कि वे इस आदेश का दिखावे के लिए तो पालन कर लेंगे, पर वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं होगा और व्यवस्था जस की तस चलती रहेगी। जब देश आजाद हुआ था तो लोगों ने सोचा था कि पुलिस की मानसिकता और काम करने के तौर–तरीके में बदलाव आएगा। स्वतंत्रता के बाद पुलिस अधिकारियों की जो पौध आई, उसमें एक जज्बा और देशसेवा की भावना थी। इसलिए कुछ वर्षों तक तो पुलिस की गाड़ी ठीक चलती रही, परंतु जैसे–जैसे समय बीतता गया, पुलिस और नेताओं के बीच साठगांठ बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए काम करने लगे। इसका वीभत्स स्वरूप हमें 1975 में इमरजेंसी के दौरान दिखा, जब पुलिस ने बहुत से ऐसे काम किए, जो उसे नहीं करने चाहिए थे। नेताओं के कहने पर फर्जी रिपोर्ट लिखी गईं,

लोगों को अकारण गिरफ्तार किया गया और तरह–तरह के अत्याचार हुए। बाद में शाह कमीशन द्वारा इनकी जांच हुई। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है तो हमें पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त करना पड़ेगा। इसी बीच 1977 में नेशनल पुलिस कमीशन का गठन हो गया। कमीशन ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली का गहन परीक्षण किया गया और विस्तृत सुझाव दिए गए। कमीशन की रिपोर्ट जब तक आई, तब तक इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गईं और चूंकि यह रिपोर्ट उनके शासन के कार्यों के आधार पर बनी थी, इसलिए उसे दरकिनार कर दिया गया।

2008 में सुप्रीम कोर्ट ने थामस कमेटी का गठन किया था, यह देखने के लिए कि 2006 के उसके आदेश का किस हद तक पालन हुआ है। कमेटी ने पाया कि सभी राज्यों में इस आदेश के पालन में उदासीनता है। पुलिस सुधार की गाड़ी लड़खड़ाती हुई चल रही है। अपेक्षाएं बहुत थीं, पर परिवर्तन नाम मात्र के हुए। सवाल यह है कि भविष्य में क्या रणनीति अपनाई जाए। मेरे विचार से तीन काम करने की जरूरत है। एक तो यह कि पुलिस अधिकारी ऐसे आंतरिक सुधारों पर ध्यान दें, जिनके लिए सरकार से न तो स्वीकृति चाहिए और न ही धनराशि का आवंटन। इससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। जब कोई आदमी अस्पताल जाता है तो उसे यह विश्वास होता है कि वहां के इलाज से उसे कुछ न कुछ फायदा होगा। इसी तरह हर व्यक्ति जो थाने जाता है, उसे यह विश्वास होना चाहिए कि यहां मेरे कष्ट का निवारण होगा। इसके लिए पुलिस को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। रिपोर्ट लिखने में जो कोताही होती है, उसे खत्म करना पड़ेगा। दूसरा काम पुलिस के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार का हो। जनशक्ति में जो कमी है, उसकी पूर्ति की जाए। वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए, संचार व्यवस्था को और आधुनिक किया जाए। फोरेंसिक लैबोरेट्रीज की संख्या में वृद्धि हो, पुलिसकर्मियों की आवासीय सुविधा बेहतर हो। इससे पुलिस की कार्यक्रमता और मनोबल, दोनों बढ़ेंगे। तीसरा काम तकनीक के अधिकतम प्रयोग का होना चाहिए। सीसीटीएनएस चल पड़ा है, इससे पुलिस के काम में बहुत सुधार हुआ है। नेटग्रिड भी काम करने लगा है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए हमें बेहतर प्रशिक्षित स्टाफ तैयार करना पड़ेगा। साइबर अपराध पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जहां प्रयोग हो सके, किया जाए। जैसे–जैसे तकनीक का प्रयोग बढ़ेगा, पुलिस की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

पुलिस सुधार की जरूरत पर जितना भी लिखा जाए, कम होगा। लोकतांत्रिक ढांचे को स्वस्थ रखने के लिए पुलिस में परिवर्तन अनिवार्य है। आर्थिक प्रगति के लिए अच्छी पुलिस व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री बार–बार विकसित भारत की बात करते हैं, पर विकसित भारत के लिए पुलिस को भी तो विकसित होना पड़ेगा। यह विकास पुलिस में संस्थागत परिवर्तन के बिना नहीं हो पाएगा। आज की शासकीय पुलिस को हमें जनता की पुलिस के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा।

दिखती है हिंसा की साजिश

अवधेश कुमार

अचानक उत्तर प्रदेश से निकलकर देश के अलग–अलग शहरों में 'आई लव मोहम्मद' के प्ले कार्ड, बैनर लगने लगे और सैकड़ों की संख्या में लोग उग्र प्रदर्शन करते चले गए। समझना कठिन था कि आखिर ऐसा हुआ क्या है? दो–तीनों के अंदर पूरे देश में डर पैदा करने वाली तस्वीर को हरने लगी।

कई शहरों से हिंसा की खबरें आने लगी और बरेली इसमें शीर्ष पर था। अंततः बरेली के साथ अन्य शहरों में साफ दिख रहे मजहबी हिंसा व आगजनी के खतरों से प्रदेश को बचाने के लिए पुलिस ने उस मौलाना तौकीर राजा को गिरफ्तार किया, जिसे इस बात का गुमान था कि वह इस्लाम के नाम पर कुछ भी करेगा प्रशासन उसे छू नहीं सकती। पुलिस ने वैसे युवाओं को भी काफी संख्या में उठाया, जो पुलिस से लड़ रहे थे, बैरिकेड तोड़ रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे या उन तरीकों से उन्मादी हिंसक मशीन बने हुए थे। भारत में किसी को भी आस्था के साथ जीने का अधिकार है। पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति किसी तरह का अपमान कानून की दृष्टि में अपराध होगा और सजा मिलेगी। किंतु ये प्रदर्शन तभी जायज होते जब किसी मुसलमान को मोहम्मद साहब का सम्मान करने या प्यार का इजहार करने से रोका गया। होता। ऐसा वातावरण बनाया गया मानो उत्तर प्रदेश के कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' कहने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई हो, पुलिस कार्रवाई कर रही हो।

क्या ऐसा कुछ हुआ? ऐसा हुआ ही नहीं। तूफान खड़ा किए जाने के बाद कानपुर के तीन सपा विधायक कानपुर पुलिस आयुक्त से मिले पूरा रिकार्ड देखा और स्पष्ट बयान दिया। एक सपा विधायक हसन रूमी ने कहा कि मुकदमा 'आई लव मोहम्मद' का बैनर लगाए जाने को लेकर नहीं हुआ है। समाज में भ्रांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि निर्दोष लोगों को आरोपी बनाया गया है और मुकदमे वापस लिये जाने चाहिए। दूसरे सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि कुछ लोग पेशेवर बवाली हैं, जिनका काम ही समाज में भ्रांति पैदा कर बवाल करना है। ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जानी चाहिए। कानपुर में कम और कानपुर से बाहर और दूसरे देशों में विरोध हो रहा है। पेशेवर उन्मादी लोग चाहे बारावफात हो या दीपावली, उसमें उन्माद फैलाते हैं। विधायक नसीम सोलंकी ने कहा कि चार सितम्बर को बारावफात जुलूस को लेकर पुलिस को कुछ भ्रांतियां हुई। 'आई लव मोहम्मद' के खिलाफ कोई एफआइआर नहीं हुई। दूसरे दिन कुछ विवाद को लेकर एफआइआर हुई है। उन्होंने भी मुकदमा वापस लेकर विवाद को समाप्त करने की अपील की। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि 'आइ लव मोहम्मद' पर न मुकदमा है। न था और न कोई लिख सकता है। प्राथमिकी में केवल विवरण में जिक्र इसलिए है कि वादी ने शिकायत में उल्लेख किया है। जरा सोचिए, ये कौन लोग हैं जो मजहब के नाम पर बार–बार पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकने पर उतारू हो जाते हैं। घटना के बारे में जितनी जानकारी है उसके अनुसार चार सितम्बर को रावतपुर के सैय्यदनगर में बारावफात पर एक गेट

परंपरागत रास्ते से अलग लगाया गया और इसी पर 'आइ लव मोहम्मद' लिखा लगा था।

इसका विरोध हुआ तो लगाने वाले आगे और दबंगई करने लगे। पुलिस ने मामला शांत करने की कोशिश की। ऐसा लगा भी कि शांत हो गया है। दूसरे दिन इसी स्थान पर बरावफात जुलूस के दौरान भंडारे का एक बैनर फाड़ा गया। एक धर्म के विरुद्ध नारा लगाने का भी आरोप हिन्दुओं ने लगाया है। ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा तहरीर में साफ लिखा है कि मुकदमा परंपरा से हटकर बिना अनुमति गेट लगाने को लेकर किया गया है। जरा सोचिए, हुआ कुछ और जो हुआ नहीं उसके आधार पर उत्तर प्रदेश और देश में सांप्रदायिक आग लगाने की कोशिश करने वाले कौन हो सकते हैं? क्या कोई मजहब इस तरीके से झूठ बोलकर लोगों को हिंसा के लिए भड़काने, उत्तेजना पैदा करने की अनुमति देता है? अगर नहीं देता है तो ये लोग इस्लाम के मानने वाले हैं या उसके दुश्मन? असदुद्दीन ओवैसी बार–बार आग लगाने वाला बयान दे रहे हैं कि नबी से मोहब्बत को रोका जाएगा तो एक–एक मुसलमान कुर्बान हो जाएगा। किसे रोका गया, कहाँ रोका गया यह तो कोई बताए? क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या मजहब के नाम पर झूठ बोलकर इनको उन्माद फैलाने, हिंसा करने और सरेआम सिर काटने का नारा लगाने की छूट मिलनी चाहिए?

सही है कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा या योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं होती तो ऐसी कार्रवाई संभव नहीं थी। अतीत के अनुभव बताते हैं कि इनको जुलूस निकालने की पूरी अनुभूति होती और जिन पुलिस वालों ने तहरीर लिखा उनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाती। बरेली में तौकीर रजा और उनके लोगों को कोई पुलिस वाला छू देता तो उसकी शामत आ जाती। इनका चरित्र देखिए । पुलिस द्वारा पकड़े गए युवकों के कुछ वीडियो वायरल है। इनमें सब हाथ छोड़कर मिडि रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, छोड़ दीजिए, अब ऐसा नहीं करेंगे। पहले का वीडियो देखिए किस ढंग से नारे लगाते पुलिस के साथ भीड़ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे, हैं पुलिस का बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें ऐसा लगता है जैसे ये मजहब के लिए जान लेने और जान देने को उतारू है। अगर मजहब के साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए निकले हैं तो आपको सजा भुगतने में डर नहीं होना चाहिए।

फिर आप माफी क्यों मांग रहे हो? साफ है कि इनका इस्लाम और मजहब से कोई लेना– देना नहीं बार–बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं और उसके बाद कार्रवाई होती है तो यह पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है। छांगुर भी गिरफ्तार हुआ, लेकिन तब तक वह इस्लाम मजहब में परिवर्तन के बड़े कॉर्पोरेट जैसा तंत्र स्थापित कर चुका था। आगरा से इसी प्रकार की घटना आई। भाजपा सरकार में ये कैसे घटित होते रहते हैं और प्रशासन की नजर नहीं जाती? इसका उत्तर देश को मिलना चाहिए। वैसे भी जिन्हें गिरफ्तार करेंगे उनके पक्ष में न्याय की लड़ाई लड़ने से लेकर झूठ दुष्प्रचार अभियान चलाने वाली प्रभावी फौज उतर जाती है।

किसानों के लिए वरदान है नया जीएसटी

शिवराज सिंह चौहान

खेती सरल हो, उत्पादन लागत घटे और किसान को अधिक मुनाफा हो, इसके लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। अन्नदाताओं का जीवन बदलना और कृषि को विकसित बनाना प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य भी है और संकल्प भी हाल में जीएसटी परिषद द्वारा किए गए संशोधन किसान हितैषी सोच को दर्शाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जीएसटी में नेक्स्ट जेनरेशन रिफार्म का जो संकल्प लिया था, आज वह नए भारत की समृद्धि का आधार बन रहा है। देश की आम जनता और किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जीएसटी दरों में जो व्यापक सुधार किए गए, वे कृषि व्यवस्था को गति और किसानों को प्रगति देने वाले हैं। इन सुधारों से देश के 10 करोड़ से अधिक सीमांत किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। पहले जहां कृषि उपकरणों पर 18 प्रतिशत तक जीएसटी देना पड़ता था, वहीं अब यह दर घटाकर केवल 5 प्रतिशत कर दी गई है। इसका मतलब है कि हर किसान को हजारों रुपये की सीधी बचत होगी। यदि कोई किसान 35 हार्सपावर का ट्रैक्टर खरीदता था तो पहले उसे लगभग 6.5 लाख रुपये खर्च करने पड़ते थे। अब यही ट्रैक्टर करीब 6.09 लाख रुपये में मिलेगा। यानी लगभग 41 हजार की बचत होगी। 45 एचपी ट्रैक्टर पर करीब 45 हजार और 50 एचपी ट्रैक्टर पर 53 हजार रुपये की सीधी बचत होगी। बड़े 75 एचपी ट्रैक्टर पर लगभग 63 हजार रुपये का लाभ होगा। ट्रैक्टर ही नहीं, पावर टिलर पर करीब 12 हजार, धान रोपण यंत्र पर 15 हजार और थ्रेशर पर लगभग 14 हजार रुपये की राहत मिलेगी। पावर वीडर और सीड ड्रिल जैसे उपकरणों पर भी 5 से 10 हजार रुपये तक की बचत होगी। जीएसटी सुधारों से कटाई और बोआई की बड़ी मशीनें भी किसानों को सस्ते में उपलब्ध हो सकेंगी। 14 फीट कटर बार पर करीब 1.87 लाख, स्क्वायरबेलर पर 94 हजार और स्ट्रारीपर पर करीब 22 हजार रुपये बचेंगे। मल्चर, सुपरसीडर, हैप्पीसीडर और स्प्रेयर भी सस्ते हुए हैं।

कृषि को अधिक लाभदायक बनाने के लिए मशीनीकरण जरूरी है। स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, कटाई मशीन, हाइड्रोलिक पंप और कलपुर्जों पर टैक्स घटने से सीमांत किसान भी आसानी से आधुनिक उपकरण खरीद पाएंगे। इससे श्रम लागत कम होगी, समय बचेगा और उत्पादकता बढ़ेगी। खेती के खर्च में कमी आने से स्वाभाविक रूप से किसान की आमदनी में वृद्धि होगी। ये अनुमानित कीमतें हैं। कंपनियों और राज्यों की नीतियों के आधार पर थोड़ी–बहुत भिन्नता संभव है, लेकिन यह तय है कि किसानों की लागत घटेगी और फायदा निश्चित मिलेगा।

किसानों को घटी हुई दरों का लाभ तुरंत मिले, इसके लिए मैंने कृषि मशीन निर्माताओं के संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। ये सुधार केवल किसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की आर्थिक चक्रीयता और आत्मनिर्भरता के लिए अभिनंदनीय कदम हैं। कृषि की लागत घटने से किसान अपनी उपज से अधिक लाभ कमा पाएंगे, जिससे उनकी

आमदनी में वृद्धि होगी। इसका सकारात्मक असर लघु और कुटीर उद्योगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कच्चा माल सस्ते में उपलब्ध होगा और उत्पादन लागत घटेगी। साथ ही एमएसएमई क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कृषि एवं पशुपालन एक–दूसरे के पूरक हैं। मधुमक्खी पालन, डेरी, पशुपालन और सहकारी समितियों को जीएसटी में जो छूट दी गई है, उससे ग्रामीण आर्थिकी में नई समृद्धि आएगी। जब किसानों के खर्च कम होंगे और उनकी आय बढ़ेगी, तो वे अपनी जीवनशैली, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक निवेश कर सकेंगे, जिससे जीवन का चहुंमुखी विकास संभव होगा। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि की ओर बढ़ रही है, तब किसानों को सस्ते दामों पर जैव कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। इससे किसान रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहने के बजाय धीरे–धीरे जैविक उर्वरकों की ओर बढ़ेंगे। मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, धारती मां का स्वास्थ्य सुधरेगा और किसानों की लागत भी कम होगी। किसानों की जोत का आकार छोटा है, इसलिए हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग और कृषि संबद्ध क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि किसानों की आय तेजी से बढ़े।

जीएसटी सुधारों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को राहत मिली है। कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स में निवेश बढ़ने से किसानों की उपज लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी और प्रसंस्करण के बाद उसे बेहतर दाम मिलेगा। प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि वे किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों के विरुद्ध किसी भी नीति और समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। जीएसटी सुधार इसी संकल्प का प्रमाण है। इससे विदेशी वस्तुओं पर हमारी निर्भरता घटेगी और 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को बल मिलेगा। ग्रामीण भारत की समृद्धि का आधार स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें हैं। जीएसटी सुधारों से इन समूहों और एमएसएमई की लागत घटेगी, जिससे गांवों और कस्बों में छोटे उद्योग पनपेंगे। ग्रामीण उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए गांवों में प्रसंस्करण इकाइयां, भंडारण और परिवहन सुविधाएं विकसित होने से विकसित और आत्मनिर्भर भारत को नई दिशा मिलेगी। कर घटने से बिक्री बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवा गांव में रहकर ही आत्मनिर्भर बन पाएंगे। जीएसटी सुधार स्वदेशी से समृद्धि के संकल्प को सार्थक करेंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था श्लांग लिव इकोनमीश बनेगी। ये सुधार किसान, छोटे व्यापारी, पशुपालक, मछुआरे और कुटीर उद्योग चलाने वाली बहनों के जीवन में नई ऊर्जा भरने का पुण्य प्रयास हैं। हमारी सरकार 'सबका साथ–सबका विकास' और अंत्योदय के संकल्प के साथ यही सिद्ध कर रही है कि खेत–खलिहान की खुशहाली ही राष्ट्र की प्रगति का पर्याय है। अबकी बार पूरा देश 'स्वदेशी से समृद्धि' के संकल्प के साथ दीपावली मनाएगा। घर–घर स्वावलंबन के दीप जलेंगे, कुटीर उद्योगों से जय स्वदेशी का मंगल स्वर गूंजेगा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे किसान विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे।

भारत–रूस संबंध

अमित सोमवंशी

स्वतंत्र भारत के विदेश नीति के जनक पंडित जवाहर लाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को भारतीय विदेश नीति के एक मजबूत स्तम्भ के रूप में स्थापित किया। तत्कालीन गुटनिरपेक्षता को दोनों ध्रुवों से समान दूरी के रूप में व्याख्यायित किया गया जबकि कालांतर में गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य भारतीय हितों की रक्षा के लिए दोनो ध्रुवों से समान नजदीकी में है। तत्कालीन नव स्वतंत्र भारत के पास दोनो ध्रुवों में बटे विश्व में तीसरे विश्व के नेता के रूप में स्थापित होने का सुनहरा अवसर था और इस अवसर में भारत को स्थापित करने में गुटनिरपेक्षतार ने मजबूत स्तम्भ का कार्य किया। गुटनिरपेक्षता की इस नीति के प्रारंभिक दिनों में ही भारत के विदेश नीति की नींव को मजबूत करने में रूस (तत्कालीन सोवियत रूस) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत–रूस (तत्कालीन सोवियत रूस) संबंधों की शुरूआत स्वतंत्रता के तुरंत बाद पण्डित विजय लक्ष्मी को प्रथम भारतीय राजदूत बनाकर रूस भेजने से किया गया। पण्डित विजय लक्ष्मी को नियुक्ति ही रूस के साथ संबंधों की महत्व को बयान करने के लिए काफी है। हालांकि स्टालिन के प्रारंभिक तल्खी के पश्चात डा. सर्वपल्ली राधा कृष्णन के राजदूत नियुक्त होने पर 1949 में सोवियत संघ से औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुआ। सोवियत संघ ने गटनिरपेक्ष नीति को समर्थन दिया और भारत की स्वयत्त विदेश नीति की सराहना की।

1950 के दशक में भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में सोवियत संघ की प्रेरणा व सहयोग से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किया गया। सोवियत संघ ने भारी उद्योग, विज्ञान, उर्जा तकनीकी क्षेत्रों में सहायता प्रदान की । 1955 में स्थापित भिलाई इस्पात संयंत्र इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। सोवियत संघ ने रक्षा सहयोग, तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक अनसंधान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की मदद की।

1955 में सोवियत नेता निकिता और बल्गानिक ने भारत का दौरा किया तथा इसी वर्ष नेहरू ने भी सोवियत संघ की यात्रा की। यह दोनो देशों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना को मजबूत किया। बैश्विक मंचों पर कश्मीर मुद्दे को लेकर कई बार सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन किया जबकि भारत ने भी कई मौको पर पश्चिमी दबाव के बावजूद सोवियत संघ की नीतियों के विरोध में मतदान नहीं किया, इस प्रकार गुटनिरपेक्ष होते हुए भी दोनो देशों के बीच सामंजस्य बना रहा।

सोवियत संघ संकट के दौर में भारत के साथ समर्पण भाव में खड़ा रहा। 1962 के भारत–चीन युद्ध के दौरान भारत को कटनीतिक समर्थन किया तथा हथियारों की आपूर्ति की। सोवियत संघ ने 21 जैसा लड़ाई विमान दिया तथा भारत के सैन्य अधिकारीयों को प्रशिक्षित किया। ऐसे ही 1965 के भारत–पाक युद्ध के बाद सोवियत संघ ने ताशकंद समझौते में (1966) में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच श्भारत– सोवियत मैत्री संधि (Indo Soviet Treaty of Peace, Frienndship and Coopretation) हस्ताक्षर हुए। यह संधि 20 वर्षो के लिए थी और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना था। भारी उद्योग, इस्पात संयंत्र, बिजली परियोजनाएं, तेल रिफाइनरी और मशीन निर्माण जैसे

क्षेत्रों में सोवियत तकनीक और सहायता से भारत ने कई कारखानों की स्थापना की, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला और बोकारो स्टील प्लांट जैसे प्रतिष्ठान सोवियत सहायता से स्थपित किए गए। सोवियत संघ ने भारत को मिग–21 लड़ाकू विमान तकनीक ट्रांसफर के साथ दी, जो भारत में HAL द्वारा बनाए गए। भारत को T–55 और T–72 टैक, सुखोई विमान, सतह INS Virat जैसे एयरक्राफ्ट कैरियरों के संचालन के लिए तकनीकी मदद दी गई। भारत ने सोवियत संघ से Mig–23, Mig–27 और Mig–29 जैसे उन्नत लड़ाकू विमान प्राप्त किए। पनडुब्बी संचालन और नौसेना क्षमताओं में सोवियत तकनीक और प्रशिक्षण का बड़ा यागदान रहा।

आर्थिक, सामरिक व व्यापारिक सहयोग का यह मजबूत रिश्ता सांस्कृतिक सहयोग में भी नए आयाम तक पहुचा। भारतीय फिल्में भी सोवियत संघ में काफी लोकप्रिय हई– जैसे आवारा और श्री 420। साहित्य, शिक्षा और भाषा के क्षेत्र में भी सहयोग हुआ– कई विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाने लगी और रूसी भाषा भारत में लोकप्रिय हुई। शीतयोद्धत्तर विश्व में सोवियत संघ विघटन (1991) के बाद भारत को अपने राने रणनीतिक साझेदार की जगह नए रूस के साथ संबंधों की फिर से परिभाषित करना पड़ा। 1991 में दोस्ताना संबंधों और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि द्विपक्षीय सहयोग का नया आधार बनी। भारत ने रूस को सबसे पसंदीदा राष्ट्र (Most Favored Nation) का दर्जा दिया। 2000 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान श्रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) की घोषण हुई। भारत ने रूस से सुखोई–30, मिग–29, टी–90 टैक और मोस मिसाईल प्रणाली प्राप्त की। रूस ने भारत में कई रिएक्टर बनाने में मदद की, कडनकुलम परमाणु संयंत्र रूस की मदद से बना। भारत ने रूस में तेल और गैस परियोजनाओं में निवेश किया (जैसे कि सखालिन–1 प्रोजेक्ट)। 2010 में द्विपक्षीय संबंधों को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी (Special and Preivileged Strategic Partnership) का दर्जा दिया गया।

वर्ष 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच व्यक्तिगत मित्रवत संबंधों ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत किया है। दोनों नेता नियमित रूप से द्विपक्षीय वार्ताएं, शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स, एससीओ जैसे मंचों पर मिलते रहे है। रूस ने भारत को एस–400 मिसाईल रक्षा प्रणाली देने का समझौता किया, जिससे पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका की नाराजगी भी हुई। एस–400 मिसाईल रक्षा प्रणाली की डील 2018 में की गई थी, जिसकी डिलीवरी 2021 में शुरू हुई। यह डील भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का संकेत भी है, क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंधों (CAAT- SA) के बावजूद यह समझौता हुआ। भारत ने मेक इन इंडिया के तहत रूस के साथ संयक्त रूप से हथियारों को निर्माण पर बल दिया है–जैसे कि AK–203 राइफल। ब्रह्मोस मिसाईल, सुखोई– 30MKI और T90 टैकों जैसे संयक्त रक्षा कार्यक्रम पहले से चलते आ रहे है, और इन्हें और बढ़ाया गया है। संयक्त सैन्य अभ्यास (जैसे इंद्र अभ्यास) नियमित रूप से होते रहे। दोनो देशों ने 2025 तक $30 बिलियन द्विपक्षीय व्यपार और $50 बिलियन निवेश का लक्ष्य रखा है। रूपया–रूबल व्यपार (डॉलर के बिना व्यपार) को लेकर बात–चीत हो रही है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण। भारत और रूस ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भी भागीदारी की और भारत ने रूस के सुदूर पूर्व (Far East) में निवेश की प्रतिबद्धता जताई, एक लाईन ऑफ क्रेडिट (1 बिलियन डॉलर) देने की घोषणा की थी। भारत और रूस BRICS, SCO, G–20 जैसे मंचों पर सहयोग करते रहे है। रूस ने भारत के न्छै स्थायी सदस्य बनने के प्रयासों का समर्थन किया है। हालांकि भारत–रूस के संबधों में कछ बहुत प्रभावशाली चुनौतियाँ भी है जो कि समय समय पर समस्याए उत्पन्न करती है। भविष्य में भी यह साझेदारी । आपसी हितों, विश्वास और सहयोग पर आधारित रहकर और आर्थिक सम्पन्नता की ओर अनबरत रूप से बढ़ते रहने की संभावना रखती है।

एक–दूसरे की जरूरत बने भारत–ब्रिटेन

हर्ष वी. पंत

ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीएर स्टार्मर और उनके साथ 125 सदस्यीय विशाल प्रतिनिधिमंडल भारत आ चुका है। बतौर प्रधानमंत्री यह उनका पहला भारत दौरा है। इससे पहले जुलाई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऐतिहासिक ब्रिटिश दौरे के बाद द्विपक्षीय संबंधों के दृष्टिकोण से स्टार्मर के भारत दौरे पर नजरें टिकी हुई थीं। वैश्विक उथलपुथल और टैरिफ को लेकर चल रही खींचतान ने भी इस दौरे का महत्व और बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के ब्रिटिश दौरे पर जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, इस दौरे पर उनकी प्रगति की समीक्षा के साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों को नए आयाम दिए जाने की व्यापक रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के इतने बड़े दल के साथ स्टार्मर का आना इस दौरे की महत्ता को ही दर्शाता है। इस समय ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जिन चुनौतियों से जूझ रही है उन्हें देखते हुए यह स्वाभाविक है कि उनसे निपटना सरकार की प्राथमिकता में होगा, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भी प्रभावित हो रही है। इसलिए स्टार्मर चाहेंगे कि वे इस दौरे को अधिक से अधिक सार्थक बनाकर ही स्वदेश लौटें।

स्टार्मर के दौरे के कार्यक्रम की रूपरेखा से ही यही संकेत मिलते हैं कि आर्थिक– रणनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंध इसके मूल में हैं। चाहे दौरे के लिए भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई का चयन हो या उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात, सीईओ फोरम में भागीदारी हो या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में सहभागिता या भारतीय फिल्म निर्माण से जुड़े केंद्रों का अवलोकन, इन सभी गतिविधियों की आर्थिक एवं सांस्कृतिक कड़ियां जुड़ी हुई हैं। जुलाई में पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे पर जिस मुक्त व्यापार समझौते पर बात बनी थी, उसे प्रभावी बनाने से जुड़ी चर्चा भी इस दौरे के एजेंडे में शामिल है। इस बीच, ब्रिटिश कंपनियों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की बात भी प्रमुखता से हो रही है, जिससे आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे ब्रिटेन की आर्थिकी को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है।

यह दौरा उस पहलू को भी रेखांकित करता है कि भारत–ब्रिटेन संबंध अतीत की औपचारिकताओं से आगे बढ़कर व्यावहारिकता और परस्पर लाभ एवं विश्वास पर केंद्रित हो चले हैं। एक समय दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक संबंधों और प्रवासियों से तय होते थे, लेकिन अब ये उन बंदिशों से बाहर निकलकर भारत–ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी जैसी पहल से निर्धारित हो रहे हैं। इसके तहत दोनों देशों ने वर्ष 2035 तक कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके जरिये व्यापार एवं निवेश, तकनीकी समन्वय एवं रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साझा प्रयास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का उन्नयन और लोगों के बीच बेहतर सामाजिक संपर्क जैसे बिंदु शामिल हैं। इस दौरे पर इन पहलुओं की समीक्षा होना स्वाभाविक है। इसमें भी व्यापार एवं निवेश और सामरिक रणनीति के ही मुख्य रूप से केंद्र में रहने के आसार हैं।

दोनों देशों ने अपने व्यापार को बढ़ाकर जल्द ही 42 अरब पाउंड तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसमें मुक्त व्यापार समझौते की भूमिका अहम होने वाली है। करीब तीन साल के अथक प्रयासों के बाद अमल में आया यह व्यापार समझौता इतनी ठोस बुनियाद पर किया गया है कि अब जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर चर्चा हो रही

है, उसमें यही समझौता मानक बन गया है। इससे मिलने वाले परस्पर लाभ को इसी से समझा जा सकता है कि जहां ब्रिटेन के एल्कोहल उद्योग एवं वाहन उद्योग की भारत जैसे बड़े एवं उभरते बाजार में पहुंच बनेगी, वहीं भारत के कपड़ा, चमड़ा एवं रत्न– आभूषण जैसे व्यापक श्रम खपत वाले उद्योगों को ब्रिटेन जैसे आकर्षक बाजार में पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी। ट्रंप की आक्रामक नीतियों के इस दौर में यह समझौता और अधिक उपयोगी साबित होता दिख रहा है।

भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ते समन्वय के बीच कुछ गतिरोध अभी भी बने हुए हैं। जैसे व्यापार समझौते के बावजूद ब्रिटेन में भारत के स्टील एवं फर्टिलाइजर उत्पादों को लेकर कुछ हिचक का माहौल है। इसके पीछे इन उद्योगों के कार्बन उत्सर्जन को एक कारण बताया जा रहा है। इसी तरह भारत में ब्रिटिश कानूनी सेवाओं को लेकर भी विरोध के स्वर सामने आए हैं। व्यापार समझौते के बाद उम्मीद बंधी थी कि भारतीय पेशेवरों के लिए ब्रिटेन जाने की राह और सुगम होगी, लेकिन उसमें अपेक्षित रूप से सकारात्मकता नहीं देखी जा रही है। संभव है कि स्टार्मर के दौरे पर इन बिंदुओं को लेकर भी कुछ चर्चा के साथ कोई स्वीकार्य समाधान निकालने की दिशा में प्रयास किए जाएं।

सामरिक सहयोग भी द्विपक्षीय संबंधों के केंद्र में बना हुआ है। चूंकि दोनों देश कई बिंदुओं पर साझा सोच रखते हैं, इसलिए सहयोग का मोर्चा भी सुगम दिखता है। समकालीन वैश्विक परिस्थितियों को भांपते हुए ब्रिटेन ने भी हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने का समझदारी भरा रुख अपनाया है। इस क्षेत्र में भारत का प्रभाव उसे एक स्वाभाविक साझेदार बनाता है, जो पिछले कुछ समय में ब्रिटेन के साथ बढ़ रही सक्रियता में नजर भी आ रहा है। हिंद–प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों को लेकर भी दोनों देश एकसमान दृष्टिकोण रखते हैं। चीन की बढ़ती आक्रामकता पर अंकुश से लेकर सामुद्रिक आवाजाही को सुगम एवं सुरक्षित बनाने से लेकर आपूर्ति श्रृंखलाओं में स्थायित्व और संतुलन को लेकर भी दोनों देश एक ही धरातल पर दिखते हैं। सामरिक मोर्चे पर संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में रक्षा तकनीक साझेदारी और रक्षा उत्पादन को लेकर भी कोई सहमति बन सकती है। साथ ही खुफिया सूचनाओं को साझा करने की राह में भी अवरोध दूर किए जाने के पूरे प्रयास होंगे। बदलते वैश्विक ढांचे और परिस्थितियों में भारत–ब्रिटेन साझेदारी की निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका होगी। स्टार्मर का यह दौरा इस साझेदारी को गति प्रदान करने का काम करेगा।

ट्रम्प टैरिफ नीति और भारत की सूझबूझ

राजकुमार मिश्र

भारत और अमेरिका के संबंधों का इतिहास उतार–चढ़ाव भरा रहा है। कभी मतभेदों की खाई इतनी गहरी रही कि एक–दूसरे की नीतियों पर सवाल उठाए जाते रहे, तो कभी सामरिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी के नए अध्याय खुलते रहे। बीते दशक में यह रिश्ता परिपक्वता की ओर बढ़ा है, परंतु जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने (2017–2021), तब इस रिश्ते ने एक नई कसौटी का सामना किया। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ट्रंप ने जो आर्थिक संरक्षणवाद अपनाया, उसने भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर डाला। परंतु भारत ने अपनी सूझबूझ और संयम से इस चुनौती को अवसर में बदलने की दिशा दिखाई।

ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और टैरिफ युद्ध : ट्रंप प्रशासन का मूल मंत्र था Buy America, Hire American । इस नीति के अंतर्गत अमेरिका ने अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा और रोजगार सृजन के लिए विदेशी वस्तुओं पर आयात शुल्क (टैरिफ) बढ़ाए। इस संरक्षणवादी रुख के चलते भारत पर भी प्रभाव पड़ा। ट्रंप प्रशासन ने भारत से आयातित स्टील और एल्युमिनियम पर क्रमशः 255 और 105 तक के टैरिफ लगाए। इसके अलावा 2019 में अमेरिका ने भारत को Generalized System of Preferences (GSP) की सूची से हटा दिया, जिसके अंतर्गत भारत को अमेरिकी बाजार में लगभग 2000 से अधिक वस्तुओं पर शुल्क–मुक्त निर्यात की सुविधा मिलती थी। यह कदम भारत के लिए झटका था क्योंकि इससे भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों के निर्यात पर असर पड़ा। अमेरिका भारत का एक बड़ा व्यापारिक भागीदार है सालाना व्यापार लगभग 150 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ऐसे में टैरिफ बढ़ोतरी ने भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को प्रभावित किया।

भारत की सूझबूझ की नीति : हालांकि भारत ने इस पूरे प्रकरण को टकराव की दृष्टि से नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन विदेश मंत्रालय ने रणनीतिक संयम की नीति अपनाई। भारत ने न तो तत्काल कोई कठोर जवाबी कदम उठाया, न ही संबंधों में तल्खी आने दी। इसके बजाय भारत ने व्यापार वार्ता और कूटनीति के जरिए मुद्दों का समाधान खोजने का प्रयास किया। भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डायलॉग्स शुरू किए, जिनमें व्यापार संतुलन, बाजार पहुंच और निवेश के मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह वैश्विक मुक्त व्यापार व्यवस्था में विश्वास रखता है, परंतु अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार भी रखता है। भारत ने अपने निर्यात को विविधता देने, दक्षिण एशिया, यूरोप और दक्षिण–पूर्व एशिया के बाजारों में नए अवसर तलाशने की रणनीति अपनाई ।

भारत की कूटनीतिक दृढ़ता : भारत की विदेश नीति में परिपक्वता का उदाहरण यह भी है कि ट्रंप प्रशासन के साथ कठिन आर्थिक मुद्दों के बावजूद सामरिक संबंधों में कोई कमी नहीं आई। अमेरिका ने भारत को हिंद–प्रशांत रणनीति में एक महत्वपूर्ण भागीदार माना। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग बढ़ता रहा। 2018 में "COMCASA" (Communications Compatibility and Security Agreement) जैसे समझौते जिनसे भारत को उन्नत अमेरिकी सैन्य तकनीक तक पहुंच मिली। भारत ने अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग भी बढ़ाया। अमेरिका से कच्चे तेल और एलएनजी (Liquefied

Natural Gas) की आयात मात्रा में भारी वृद्धि हुई। इससे भारत ने अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया।

भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा : ट्रंप टैरिफ नीति ने भारत को एक गहरा संकेत दिया कि किसी भी वैश्विक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालिक रूप से जोखिमपूर्ण हो सकती है। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति दी। यह न केवल घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का कार्यक्रम था, बल्कि यह आर्थिक स्वतंत्रता की नीति का भी हिस्सा था। सरकार ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियानों को नवीनीकृत रूप से लागू कर विदेशी निर्भरता घटाने का प्रयास किया। भारत ने इस अवसर को सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के रूप में भी देखा यानी चीन पर निर्भर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में खुद को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना। ट्रंप की चीन–विरोधी नीति के चलते अमेरिका ने भी भारत में निवेश की संभावनाएं तलाशीं, जिससे भारत को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला।

नीति और आर्थिक संतुलन की कला : भारत की नीति–निर्माण प्रक्रिया में सबसे बड़ा गुण रहा है संतुलन। जब एक ओर अमेरिका ने व्यापारिक मोर्चे पर सख्ती दिखाई. वहीं भारत ने यह सुनिश्चित किया कि संबंध पूरी तरह से व्यापारिक विवाद तक सीमित न रह जाएं। रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग जारी रहा। भारत ने अमेरिका के साथ 2 अ2 वार्ता की परंपरा को जारी रखा, जिसमें विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर संवाद होता है। इस संवाद ने दोनों देशों के बीच सामरिक समझ और विश्वास को मजबूत किया। इसके साथ ही भारत ने अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए विश्व व्यापार संगठन (ज्ञ) में भी अपनी स्थिति स्पष्ट की कि संरक्षणवादी नीतियां वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचाती है। भारत–अमेरिका संबंधों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जन–जन के रिश्ते। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का बड़ा समुदाय (करीब 45 लाख) रहता है, जो दोनों देशों के बीच सेतु का काम करता है। यही भारत की सूझबूझ है जो हर संकट को अवसर में बदलने की कला जानती है।

पूर्व सैनिक सेवा परिषद गीत

हम भारत के पूर्व सैनिक,
नई प्रेरणा लाये हैं।
देश की रक्षा करते थे,
अब इसे सजाने आये हैं।
बर्फ की चोटी, तपती रेती,
सागर हो या हो खाई।
शत्रु पोत और टैंक विमानों,
की देखो शामत आई।
भारत के जल–थल नभ सारे,
सदा बचाते आये हैं।। हम...
समर भूमि से कर्म भूमि को,
अब हम बढ़ते जायेंगे।
छुआ–छूत और ऊँच–नीच को,
जड़ से दूर भगायेंगे।
अपना भारत सुखी बली हो,
शिव संकल्प संजोये हैं।। हम...
सामाजिक समभाव सुरक्षा,
निर्बल क्यों भयभीत रहें।
सन्तति हैं सब भारत मां की,
सबके मन में प्रीति रहे।
संगठना में महाशक्ति है,
मंत्र यही अपनाये हैं।। हम...
अपने श्रम, अपने पौरुष से,
सब बाधायें दूर करें।
सद्शिक्षा और सद्विचार से,
मानवता को पुष्ट करें।
महान राष्ट्र था, पुनः बनेगा,
लक्ष्य यही ले आये हैं।।
हम भारत के पूर्व सैनिक,
नई प्रेरणा लाये हैं।
!!भारत माता की जय !!

हमारे उद्घोष

पूर्व सैनिक– जिन्दाबाद, जिन्दाबाद
पूर्व सैनिक आयें हैं– नई रोशनी लायें है।
पूर्व सैनिक की क्या पहचान– सेवा, साहस और सम्मान

यथार्थ के युग प्रवर्तक लेखक

अनुराग शुक्ल

भारतीय साहित्य के आकाश में अनेक नक्षत्रों ने अपनी प्रतिभा से प्रकाश फैलाया, परंतु उनमें एक नक्षत्र ऐसा है जिसकी चमक आज भी अक्षुण्ण है– वह है कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य को न केवल नई दिशा दी, बल्कि समाज के हर वर्ग की भावनाओं, संघर्षों और पीड़ाओं को अपनी लेखनी के माध्यम से स्वर दिया। प्रेमचंद का साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज का दर्पण है जिसमें भारत के जनजीवन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है।

मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, जबकि 'नवाब राय' और बाद में 'प्रेमचंद' उनका साहित्यिक नाम बना। बचपन से ही प्रेमचंद का जीवन संघर्षो से भरा रहा। उनके पिता मुंशी अजायब राय और माता आनन्दी देवी थी। जब वे केवल 8 वर्ष के थे, तभी मां का निधन हो गया और पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिससे प्रेमचंद को स्नेह का अभाव महसूस हुआ। गरीबी के कारण उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कठिन परिस्थितियों में प्राप्त की। वाराणसी के क्वींस कॉलेज से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे चलकर अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री ली। नौकरी की, परंत साहित्य सेवा के कारण उन्होंने सरकारी बंधनों से मक्त होकर लेखन को ही जीवन का लक्ष्य बनाया।

प्रेमचंद की साहित्यिक यात्रा उर्दू कहानी 'सोज–ए–वतन' से आरंभ हुई, जो 1908 में प्रकाशित हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे देशभक्ति भड़काने वाला साहित्य मानकर जब्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने उर्दू से हटकर हिंदी में लेखन प्रारंभ किया और 'मुंशी प्रेमचंद' नाम से अमर हो गए। उनकी पहली हिंदी कहानी 'सौत' थी, परंत प्रसिद्धि 'पूस की रात', 'ईदगाह', 'नमक का दरोगा', 'कफन' और 'शतरंज के खिलाड़ी' जैसी कहानियों से मिली। उन्होंने हिंदी कहानी को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज सुधार का माध्यम बनाया। प्रेमचंद के उपन्यास उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण और

सामाजिक सरोकारों के प्रमाण है। उनके प्रमख उपन्यासों में 'सेवासदन', 'निर्मला', 'रंगभूमि', 'कर्मभूमि', 'प्रेमाश्रम', 'गोदान' और 'गबन' शामिल है। 'सेवासदन' (1918)– इस उपन्यास में उन्होंने स्त्री स्वतंत्रता और समाज में स्त्रियों की स्थिति पर गहरी चोट की। नायिका समन के माध्यम से उन्होंने समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को उजागर किया।

'निर्मला' (1927)– बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक करीतियों पर केंद्रित यह उपन्यास ह्रदय को झकझोर देता है। 'रंगभूमि' (1925) अंधे नायक सूरदास के माध्यम से प्रेमचंद ने औद्योगिक पूंजीवाद और किसान वर्ग के शोषण का यथार्थ चित्रण किया। 'गबन' (1931)– इसमें उन्होंने मध्यमवर्गीय यवकों की नैतिक दुविधा को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तत किया। 'गोदान' (1936) – प्रेमचंद का शिखर उपन्यास है। यह भारतीय ग्रामीण जीवन, किसान की व्यथा और उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति का सबसे सजीव चित्र है। होरी महतो का चरित्र भारतीय किसान का प्रतीक बन चुका है, जो जीवनभर मेहनत करता है पर सुख नहीं पाता। यह उपन्यास प्रेमचंद की विचारधारा, उनकी संवेदना और समाज के प्रति प्रतिबद्धता का चरम उदाहरण है। माना जाता है कि राम चरित मानस के बाद सबसे ज्यादा पढ़े जाना वाला यह कृति है ।

प्रेमचंद की कहानियां समाज के सबसे निचले तबके से लेकर उच्चवर्ग तक के जीवन की सच्ची झलक देती है। 'ईदगाह' में छोटे हामिद की त्याग भावना हो, 'पूस की रात' में किसान हल्क की दारुण स्थिति, 'कफन' में गरीबी से जूझते बाप–बेटे की ह्मदय विदारक कथा, या 'नमक का दरोगा' में ईमानदारी का संघर्ष– हर कहानी यथार्थ की गूंज बनकर सामने आती है। उनकी कहानियों की भाषा सरल, भावपूर्ण और जनमानस के निकट है। प्रेमचंद ने साहित्य को 'जीवन का दस्तावेज' माना और कहा श्साहित्य समाज का दर्पण नहीं, बल्कि उसका पथप्रदर्शक होना चाहिए। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद, सामंतवाद, बाल विवाह, दहेज, और शोषण जैसे मुद्दों पर खलकर लिखा। उनकी लेखनी में मजदूर–किसान वर्ग की आवाज थी। उन्होंने कहा था– हमारा साहित्य उस समाज के काम का नहीं, जो आरामकर्सियों पर बैठकर जीवन का रस लेता है, बल्कि उस समाज के काम का होना चाहिए जो मिट्टी में पसीना बहाता है। उनके लेखन ने हिंदी साहित्य को यथार्थवाद की दिशा दी, जिससे प्रेरित होकर आगे चलकर रेणु, यशपाल, नागार्जुन, अमृतलाल नागर, और फणीश्वरनाथ 'रेणु' जैसे लेखकों ने सामाजिक यथार्थ पर लेखन किया।

प्रेमचंद का जीवन 8 अक्टूबर 1936 को समाप्त हुआ, पर उनकी साहित्यिक विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां, 14 उपन्यास, अनेक निबंध और संपादकीय लेख लिखे। सत्यजीत रे ने उनके शतरंज के खिलाड़ी पर प्रसिद्ध फिल्म बनाई, जो प्रेमचंद के यथार्थ दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुंशी प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं, बल्कि यगद्रष्टा थे। उन्होंने अपनी कलम से समाज की आत्मा को छुआ, किसानों की पीड़ा, स्त्रियों के आँसू और गरीबों की बेबसी को शब्दों में ढाला। वे साहित्य में मानवता के पुजारी थे– जिन्होंने कहा था कि वह साहित्य निरर्थक है जो मनुष्य को बेहतर न बनाए। उनका जीवन सादगी, संघर्ष और सेवा का प्रतीक है। प्रेमचंद आज भी जीवित है – अपने शब्दों में, अपने पात्रों में, और उस हर ह्रदय में जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। वास्तव में, वे भारतीय साहित्य के अमर दीपक है, जो सदैव यथार्थ और मानवीय मूल्यों की राह को आलोकित करते रहेंगे।

100 years of the RSS : The sprit remains unchanged

When KB Hedgewar founded the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) in Nagpur on September 27, 1925, few could have imagined the remarkable journey it would embark on over the years. The RSS today stands as a living epitome of selfless service that has shaped India's social fabric, defended its sovereignty, empowered its vulnerable communities, and also nurtured timeless civilisational values. As the RSS celebrates its centenary, it is worthwhile to revisit its journey.

At a recent event in Delhi, RSS sarsanghchalak (chief) Mohan Bhagwat asserted, "Religion is by individual choice; there should be no allurement or force in this." This view echoes the Sangh's founding philosophy: To build a society rooted in harmony rather than conflict, collective strength rather than division, and character building, not just material wellbeing. Through daily shakha (local chapter) meetings and volunteer-driven initiatives, the RSS seeks to foster discipline, resilience, and pride in India's cultural heritage, shaping individuals who view service to the nation as their highest calling.

It was, therefore, not a surprise when Prime Minister (PM) Narendra Modi, in his speech on this Independence Day lauded the RSS for its century-long role in nation-building. He reminded Indians how the RSS stands out as one of the most influential socio-cultural movements in independent India. Independence came shrouded in the tragedy of Partition. Amid this tragedy, RSS swayamsevaks rescued, rehabilitated, and protected countless victims of the carnage. Under the leadership of the second sarsanghchalak, MS Gol- walkar, and other senior leaders, the RSS mobilised communities, set up refugee camps, provided food and medical aid, escorted vulnerable families to safety, and organised defences for besieged homes. Even Congress leaders, overwhelmed by the situation, reportedly sought the Sangh's assistance to protect their families and communities in Punjab. No wonder The Tribune called the RSS "the sword arm of Punjab".

This spirit endured beyond Partition. During the anti-Sikh riots of 1984, the RSS provided shelter and relief to the Sikh community. Acknowledging this, noted author Khushwant Singh said that the RSS played an honourable role in maintaining Hindu-Sikh unity "before and after the assassination of Mrs. Indira Gandhi".

Considering this legacy, it is unfounded and erroneous when some people accuse the RSS of being a major- itarian organisation. During Independ- ence, it helped protect India's minorities and their places of worship. In March 1947, when mobs instigated by the Muslim League headed toward the Golden Temple, RSS volunteers armed with swords and lathis confronted them, forcing a retreat. Three days later, when another assault threatened the sacred Sikh shrine, RSS swayamsevaks formed a human ring of defence and fought for hours, successfully repelling the attackers.

The RSS's role in the country's integration is even less known. From Kashmir to Goa to Dadra and Nagar Haveli, it has played a decisive role in preserving India's territorial integrity. When Pakistan-backed tribal invaders attacked Jammu & Kashmir, Sardar Vallabhbhai Patel sought Gol- walkar's help to persuade Hari Singh, the then princely state's ruler, to join India. Golwalkar travelled to Srinagar and impressed upon him the stra- tegic necessity of immediate accession. RSS volunteers also aided the Army during the 1947-48 war by managing sup- plies, logistics, and relief for refugees fleeing areas like Mirpur and Muzaffarabad.

In 1954, swayamsevaks spearheaded the liberation of Dadra and Nagar Haveli from Portuguese control. According to KR Malkani's book The RSS Story, "On 2 August 1954, some 200 RSS swayamsevaks, led by Nana Kajrekar and Sudhir Phadke, liberated Dadra and Nagar Haveli, putting to flight 175 Portuguese soldiers armed with rifles, Bren guns, and Sten guns." Similarly, the RSS joined underground freedom movements to fight for Goa's liberation.

The RSS has always fought for strengthening India. During the 1975 Emergency, the Sangh became the resistance's backbone, mobilising peo- ple to defend the Constitution. The Economist wrote in January 1976, "The shock troops of the movement come largely from the Jana Sangh and its affiliate RSS, which claim a combined membership of 10 million, of whom 80,000, including 6,000 full-time workers, are in prison." At a time when people and institutions were willing to crawl when told to merely bend, the RSS fought against authoritarianism.

The RSS has also devoted itself to uplifting tribals and marginalised com-munities. The Akhil Bharatiya Vanvasi Kalyan Ashram, founded in 1952, oper- ates more than 20,000 projects across 52,000 villages in 323 districts of the country, covering education, health care, skill development, and cultural revival. The RSS's approach has been to bring tribals into the national main- stream without compromising their original identities, bolstering their tribal pride while integrating them with the larger Indian identity.

The RSS is also often unfairly criti- cised regarding its relationship with Mahatma Gandhi. There were some differences of opinion between Gandhi and the RSS on certain issues- just as there were within the Congress itself- but it would be misleading to portray their relationship in terms of hostility or rivalry. Their differences never stood in the way of mutual regard. This was evident in 1934, when Gandhi visited an RSS camp in Wardha. He was struck by the organisation's "discipline, complete absence of untouchability, and rigorous simplicity". On September 16, 1947, Gandhi addressed an RSS meeting in Delhi, praising its spirit of service and sacrifice. The RSS too, soon after Gandhi's assassination, suspended all sha- khas for 13 days as a mark of respect- the only time in the Sangh's history.

This spirit of engagement-where differences do not preclude respect or constructive work- is reflected in the way the RSS approaches regions and communities beyond its traditional base. The Northeast, for instance, was a region marked by alienation and insurgency due to colonial duplicity and policy shortcomings after Independence. The RSS, since establishing its first sha- kha in Guwahati in 1946, has played a transformative role in bringing the region to the national mainstream.

As the RSS completes a century of service, its contribution to nation-building remains steadfast and ever-growing. A recent testament to this spirit was seen during the Covid-19 outbreak, when in May 2021, nearly 300 swayamsevaks revived the long-defunct BGML hospital in Kolar within two weeks, offering much-needed relief to hun- dreds of patients. Such examples reflect how the RSS continues to quietly perform its role as it was envisioned a century ago.

Dealing with sensitive Ladakh

Maj Gen Harsha Kakkar (Veteran)

A day after violence in Ladakh, the government dispatched a special envoy to the region, while a team of six negotiators including three each from Leh and Kargil flew to Delhi for talks. Thupstan Chhewang, the Chairman of the Leh Apex Body (LAB), stated, 'An official of the Centre has come and the signal we are getting is that they are ready to start the talks immediately.' The government intent is to send a message that violence will not stall talks as Wangchuk had desired and the government is serious in addressing genuine demands of the people.

Sonam Wangchuk, the face behind the protests in Ladakh, had in Jul this year edged out Chhewang from the Chairmanship of the LAB, in a similar manner as Kejriwal edged out Anna Hazare, after exploiting his hunger protests to form his own political party as against the wishes of an apolitical Hazare. Chhewang, similarly apolitical as Hazare, had mentioned that his reason for resigning was to stay away from 'electoral politics and partisan affiliations.'

Simultaneously, the government is acting against Wangchuk and others behind the protests. The cause of protests is claimed to be delay in grant of statehood and the sixth schedule, which are subjects already under discussion in ongoing talks between the centre, LAB and the Kargil Democratic Alliance (KDA). Most other issues have already been addressed. Simultaneously, there was no violence in Kargil, except a silent bandh to support Leh protests.

Both the LAB and KDA were once adversaries but have now joined hands to discuss aspects pertaining to Ladakh. This itself is an indicator that these subjects' merit attention. The government by engaging with both parties is sending the message that it does not favour one versus the other. It will also keep Sonam Wangchuk away from being the person who pushed the centre into accepting the demands.

The government, in retaliation to the violence has begun cracking down on foreign funding and those who instigated the violence. As a first step it has cancelled the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) licence for Wangchuk's Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh. Another Wangchuk establishment, the Himalayan Institute of Alternatives Ladakh, is facing a CBI enquiry for alleged FCRA irregularities. The message being given by the government is that it suspects foreign funding was behind the protests.

Instigating violence is a means of displaying power and this is exactly what Wangchuk has been doing, aiming to project a larger-than-life image of himself. Further, display of power shifts media attention away from investigations into corruption within institutions established by Wangchuk. Politically, as is the norm, opposition parties, including those in J and K displayed solidarity with the protestors and blamed the government for not acting.

Ladakh has always been a peaceful region and there have been no protests for over 70 years despite J and K governments ignoring development in the region. Ladakhi soldiers

have earned repute for their courage in various operations in the region. The people of the region have always stood by India in all conflicts. For Ladakh to implode there has to be a major cause or its people instigated. Speeches by Wangchuk and a few of his close allies have been provocative and threatening the Indian government.

The sensitivity of Ladakh is well known. It is a region which borders two major adversaries, both of whom would willingly support violence. The impact on national security is immense. Security forces and local residents have a close understanding. They have assisted one another whenever the need arises. Hence, the government jumped in to discuss their grievances.

New Delhi cannot accept terms and conditions as demanded by Wangchuk blindly. The demands, including statehood and inclusion into the sixth schedule will have to be modified to meet conditions prevailing in Ladakh as also those of governance. Hence the need for dialogue.

The sixth schedule was designed for North Eastern states. It cannot be implemented for Ladakh in its current form. The government, constructing roads and other infrastructure for defence, needs to control environmental clearances rather than being held hostage to power of tribal bodies.

Similarly, unless J and K is given statehood, Ladakh cannot be granted. Also, there are other options as currently with J and K. Rushing is never a solution. This is well known to those behind the protests. It appears the aim is to blame and pressurize the government into acting while giving credit to Wangchuk.

At the same time the government must understand that it needs to meet aspirations of people of the region. It cannot continue talks for eternity. It must ignore those who seek a greater role in dialogue by displaying their power to instigate violence, like Sonam Wangchuk and interact with saner voices such as Chhewang. It is a welcome step that members of both LAB and KDA have moved to Delhi for talks as also that the government has sent interlocutors to the region.

While acting against the instigators and those involved in violent protests, the innocent must not be prosecuted as it would only add to anger. Investigating foreign hands in funding institutions in sensitive Ladakh needs to be done. The region needs peace and stability as its economy depends on tourism which is the first to suffer when violence breaks out. Ladakhi's are our people and must be treated as such.

It is hoped that the violence which erupted remains a one-off incident and peace prevails in the future. Members of the KDA and LAB must send out a message of patience as also of the government's intent in finding a solution.

Why an Armed Forces Officer must be a Devilish Dare-Doer brilliant, Charming and a Seemingly Reckless Risk-Taker

- By Lal Singh Maroria

The job of an armed forces officer isn't just to command troops or enforce discipline. It's to lead men into the unknown, into places where maps end, where certainty dies, and where decisions made in seconds echo for decades.

To survive and succeed in such a world, an officer must be much more than a soldier. He must be a paradox: bold yet measured, cunning yet honourable, aggressive yet composed. And yes, devilish, daring, brilliant, charming, and even (seemingly) reckless.

Here's why these traits aren't optional, they're essential.

1. The Devilish Dare-Doer: Courage That Commands

Ask any veteran what defines a true officer, and they'll likely say: "Someone who leads from the front." That means being the first to jump, the first to take fire, the first to walk into a minefield if that's what the mission demands.

But here's the secret: this boldness isn't born on the battlefield. It's bred in the academies.

The Seeds of Boldness

Anyone who's lived the academy life, NDA, IMA, OTA , INA or AFA, knows the legends:

* The midnight raids on the cadets' cafeteria, hearts pounding, slippers flapping on tarmac, eats packets clenched like trophies of war.

NDA CADETS CAFETERIA

* Seniors crashing Greenhorn or Rovers campfires, trading tall tales and walking away with "tipsy pudding" for the Squadron under the noses of instructors.

TIPSY PUDDING

* The "perennially punished" cadet, unboxed early from the safe mould of obedience, unbroken by restrictions, and still unreformed (some say unredeemable), finishes Sinhgad route march in under 4 hours, pulls off a slick turnout, flashes a grin at the Duty JCO, and somehow makes it for outpass — freshly shaved, smartly turned out in Mufti, but utterly unstoppable with a swagger.

NDA CADETS AT SINHGAD

* The Squadron trickster who placed a pith-hat over the lightning conductor atop Sudan Block, immortalised forever in Squadron folklore.

SUDAN BLOCK

These "Panga-Takers", often written off as troublemakers, are usually the very cadets who, years later, lead units, earn gallantry medals, and innovate in crisis.

Outrageous in Peace. Outstanding in War.

2. Brilliant: A Mastermind Under Fire

Hollywood often romanticises brute strength. But in the real military, it's brains that win battles. Officers must plan logistics, interpret satellite intel, coordinate joint ops, and improvise when radios fall silent and backup fails.

Example: Field Marshal Sam Manekshaw, MC (Indo-Pak War, 1971)

Manekshaw didn't just fight battles, he orchestrated them. His strategic brilliance delayed the Indian military's response to ensure preparedness, even when pressured politically. The result? A swift, decisive victory and the creation of Bangladesh in just 13 days.

Brilliance isn't about bookish intellect. It's about clarity under fire. And yes, sometimes it begins with a cadet who bunks a class, then aces a field tactics demo, and one day becomes the Dare Devil Infantry Commander of his battalion. That blend of rebellion and refinement? It's part of the DNA.

3. Charming: The Officer as a Human Beacon

Leadership isn't just about authority — it's about influence. Troops follow orders, yes, but they follow officers when they believe in them. That belief is built on connection, approachability, humour, and empathy.

Example: General K.S. Thimayya, DSO

Known as a soldier's general, Thimayya's rapport with his men was legendary. Whether it was sharing tea in the trenches or taking the blame for others' mistakes, his charm wasn't for show, it was for strength. He made his men want to follow him, not just obey him.

Officers lead men who are cold, hungry, or

afraid. Sometimes, charm is not just a gift, it's a necessity.

4. A Seemingly Reckless Risk-Taker: Action in Ambiguity

In civilian life, risk is calculated with spreadsheets. In the military, it's often calculated with gut, experience, and instinct, under fire. Officers sometimes act in ways that seem reckless to outsiders, but those very actions save lives and change outcomes.

Example: Major Sandeep Unnikrishnan, AC (Operation Black Tornado, 2008)

During the 26/11 Mumbai attacks, Major Unnikrishnan led the NSG team into the Taj Hotel. He went in multiple times to rescue hostages, alone, in close-quarter battle with terrorists, until he was shot. His last words were: "Don't come up. I'll handle them."

To some, it looked reckless. But that act likely saved dozens of lives.

5. Balanced Madness: The Beautiful Paradox

No manual can fully prepare an officer for the battlefield. Training helps. Discipline sustains. But in the heart of chaos, when bullets fly, when a comrade is down, when the mission seems lost, it's these "paradoxical" qualities that guide action.

The devilish streak pushes forward.

The brilliance maps a path.

The charm holds the team together.

The recklessness challenges limits, and often redefines them.

PITH-HAT

Even in academies, there's a reason the "Mad Ones" are remembered:

* The cadet who placed a pith-hat over the lightning conductor atop Sudan Block? That would have been an amazing act of mountaineering for which an Arjuna Award should have been given.

* The under-punishment cadet who led cross-country despite being a three pointer and a regular at restriction roll calls.

* The Class Skipper who became academy Silver Medalist.

These are not lapses, they're indicators. Boldness, when refined, becomes battle-readiness.

6. Nurturing the Next Lions: Dare, Don't Dampen

We can't hope to build bold, fearless leaders if we follow a system that stifles daredevilry and initiative. If the hierarchy refuses to stand up for its Young Officers, if it doesn't hand-hold them through their early mistakes, their audacious dreams, and their messy, magnificent growth, how can we ever expect lions to lead from the front?

Risk-taking must be encouraged, not punished. Initiative must be groomed, not clipped. For every young officer who pushes the boundaries today, there could be a future war hero tomorrow, if only we let them be.

We must celebrate those who show spark, not just those who colour within lines. Otherwise, we'll be left with a military of managers, not leaders.

Modern Warfare Needs Modern Officers

Today's battlefields aren't just mountains and borders. They're urban zones, digital domains, counter-terror ops, disaster relief missions, and international diplomacy.

So, the Officer of today isn't just a Warfighter. He's:

* A Negotiator in insurgency-hit zones

* A Disaster Manager during floods, earthquakes, and pandemics

* A Cyber Defence Strategist

* A Peacekeeper under the UN flag

* A Military Attaché representing India abroad

Each of these roles demands not just technical skill but personality, cultivated, sharp, and situationally aware.

In Conclusion: The Officer's Code

The finest officers aren't defined by their ranks or decorations, but by their ability to rise, again and again, in the harshest of conditions, with heart, wit, and sheer will.

They dare — when others doubt.

They smile — when others falter.

They leap — when others freeze.

Because they are not just Soldiers.

They are Symbols.

And if we want more such symbols, we must protect the spark before it's stamped out. Encourage initiative. Accept chaos. Allow space for mistakes. For only then will we raise the kind of officers who Walk into Fire, and come out Forged in Glory.

BEYOND ACTIVE SERVICE

(The story of a soldier's instinct that never retire)

-Col. Hitendra Bahadur SM , (Retd.)

"Once a Soldier, Always a Soldier"

The essence of military service lies not just in tactical acumen or discipline on the battlefield, but in the core values it ingrains: loyalty, integrity, moral courage, and selfless service to the nation. These are not taught merely for professional competence—they become part of a soldier's DNA. Even after retirement, they manifest in the most unexpected places, sometimes thousands of miles from one's post, in civilian mclothes, amidst strangers.

In March 2025, while flying from Delhi to Doha on an Air India flight to begin a new assignment, I was reminded of this truth in the most profound way.

A Silent Plea at 35,000 Feet

My seat was in the 17th row, aisle. A young girl, around 22, sat in the middle, flanked by a man on the window seat. She was visibly nervous, her awkward movements hinting at her first flight experience. We didn't speak until the meal service began.

She turned to me hesitantly and asked, "Is this meal free, or do we have to pay?" Her accent gave her away. "Are you from Kashmir?" I asked.

"Yes. she replied. "I'm going toDoha to work as a home tutor. Maths, English, and Social Science. But the salary is just 1200 riyals."

As she spoke more about her family—unemployed brothers, an aging father, and her recent completion of Class 12—my concern grew. Curious about the terms of her employment, I asked if I could see her passport and visa.

To my shock, she was travelling on a tourist visa, not a work permit.

The man beside her began leaning into our conversation. When I casually mentioned that I was a retired Army officer, his body language shifted. He went quiet. Something wasn't right.

Landing into Trouble

We landed at Hamad International Airport around 10:30 PM. The man quickly disappeared. I passed through immigration, but the girl was stopped and taken aside. She looked at me, eyes wide, silently asking for help.

My instincts kicked in. I remembered the faces of the many Kashmiri soldiers who had served under me during my time raising a Home & Hearth Battalion in the Valley. This girl could be their daughter, their sister.

I approached the immigration captain. He explained the law: tourist visa holders must carry a return ticket, hotel booking, and $500 cash. She had none. "You're Indian," he said, "If you pay for her return, we'll deport her immediately. Otherwise, it's three months in detention before repatriation."

I agreed to pay. Just then, a phone rang. The captain took the call in Arabic. Suddenly, the atmosphere shifted. He returned and said, "You may go. Everything is being handled."

Three men in white thobes—dignified, stoic—arrived to take her away. Before she left, I managed to hand her a note with my contact details.

The Whispered Cry for Help

At 2:00 AM, my phone rang on WhatsAp.

"Sir, this is Hazel. My battery is low. They've taken my passport. Locked me in a room. I told them I won't work as a maid. I'm very scared."

I asked her to send her location. Along with a friend, I drove to a high-walled palace glowing in lights—no way in, guards at every gate. Realizing there was no legal way to intervene, I withdrew silently. But I didn't sleep that night. At 8:30 AM, I was at the Indian Embassy.

I narrated the entire ordeal to the Ambassador. His response was immediate and effective. Hezal was rescued and safely flown back to Srinagar via Delhi that very day.

A Father's Voice from Kashmir.

That evening, I received a call from an unknown number.

"Jai Hind, Colonel Saab. I am Mohammad Bhat from Kashmir.I am Hazel's father. (Name and location has been changed to preserve the dignity of her family) Thank you for saving my daughter's honour. If Kashmir is alive today, it is because of the Indian Army."

His words lifted me. Not for recognition—but because they reaffirmed that our Army continues to be the bridge between hope and despair for millions. His words captured what generations of service and sacrifice have built—trust.

Lessons for Young Officers

To those who wear the uniform today, I offer this as more than just a story—it's a reminder:

Leadership doesn't retire. Whether on parade ground or on a commercial flight, your presence represents the values you stood for.

Trust is built in silence. The girl never asked for help out loud. Her eyes did. A soldier sees what others miss.

Dignity is worth protecting, always. Even if it means going beyond the call, stepping into foreign terrain, or facing uncomfortable situations.

Don't underestimate your influence. Sometimes just stating who you are—"an Indian Army officer"—is enough to disrupt exploitation and restore order.

Be alert. Always. Not with suspicion, but with awareness. The world needs sentinels, even off the battlefield.

Epilogue: Soldier for Life

That day, I didn't act as a retired colonel.

I acted as a soldier for life—true to the oath, guided by the ethos, and committed to a lifetime of service.

Because while the uniform may come off, the mission never ends.

India upgrades ties with Afghanistan's Taliban

India on Friday upgraded ties with Afghanistan's Taliban administration, giving a boost to the diplomatically isolated group, by announcing it would reopen its embassy in Kabul that was shut after the Taliban seized power in 2021.

The Afghan Taliban administration will also send diplomats to New Delhi, its foreign minister said.

Get the latest news from India and how it matters to the world with the Reuters India File newsletter. Sign up here.

India closed its embassy in Kabul following the withdrawal of U.S.-led NATO forces from war-torn Afghanistan four years ago, though it launched a small mission in 2022 to facilitate trade, medical support and humanitarian aid.

About a dozen countries including China, Russia, Iran, Pakistan and Turkey have embassies operating in Kabul, although Russia is the only country to have formally recognised the Taliban administration, whose members are under U.N. sanctions including a travel ban and asset freeze.

INDIA'S MOVE INFLUENCED BY TENSIONS WITH PAKISTAN, CHINA

India's announcement came during talks in New Delhi between Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar and his counterpart in the Taliban administration, Amir Khan Muttaqi, who is on a six-day visit after getting a temporary exemption on his travel ban.

It was the first such trip to India by a Taliban leader since 2021.

"India will raise its technical mission to a diplomatic mission in Kabul, and our diplomats will also come here," Muttaqi told reporters on Friday, adding that the aim was for the two countries to slowly return to "normalcy".

India and Afghanistan have historically had

...Contd. Page-31

100 years of RSS and the three wars: 1962, 1965, 1971 — A civilisational reflection...

-Courtesy Organiser

On Vijayadashami in 1925, Dr. Keshav Baliram Hedgewar founded the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) with the conviction that Bharat's strength in the world depends first on internal unity and discipline. Hedgewar understood that a nation fragmented within could never command respect abroad, and that true sovereignty rests on cultural confidence as much as on political power. This insight was tested in Bharat's first three great wars - the 1962 conflict with China and the 1965 and 1971 wars with Pakistan.

Each of these crises not only shaped Bharat's military and diplomatic path but also revealed the RSS's worldview - that civilisational clarity, social discipline, and unity are the real anchors of national defence.

1962: The Shock of China

Guruji's Farsighted Warnings

M. S. Golwalkar ("Guruji"), the second Sarsanghchalak, was forthright about Communist China. In his book Bunch of Thoughts, section Fight to Win, he wrote:

"Firstly, we have to keep in mind that China has always been expansionist. It is in its blood. Over one hundred and fifty years ago Napoleon had forewarned not to rouse that yellow giant lest he should prove a grave peril to humanity. Seventy years ago Swami Vivekananda had specifically warned that China would invade Bharat soon after the Britishers quit."

He added with biting clarity:

"Now, added to the expansionist blood of China is the intoxicant of Communism, which is an intensely aggressive, expansionist and imperialistic ideology. Thus in Communist China we have the explosive combination of two aggressive impulses. It is a case of - already a monkey, moreover drunk with wine."

Guruji also dismissed illusions such as Panchsheel:

The slogans and paper compromise like peaceful co-existence' and 'Panchsheel' that our leaders are indulging in only serve as a camouflage for the self-seeking predatory countries of the world to pursue their own ulterior motives against our country. China, as we know, was most vociferous in its expression of faith in Panchsheel. China was extolled as our great neighbour and friend for the last two thousand years or more from the day it accepted Buddhism. Our leaders declared that they were determined to stick to China's friendship 'at all costs: Once, we had similarly resolved to win the friendship of Muslims in this land 'at all costs. How much it has cost us in terms of our national integrity and honour is all too well known. The same history has been repeated in this case also."

RSS's Service and Recognition

When war broke out, swayamsevaks stepped forward across the nation: managing traffic, assisting civil defence, donating blood, and helping families of soldiers. Their discipline was so striking that even Pandit Nehru, despite his deep political hostility towards the RSS, had to bow before their spirit of service. In a gesture that surprised many, he invited RSS swayamsevaks to march in the 1963 Republic Day Parade. It was an extraordinary moment in independent Bharat's history - the state compelled to recognise the very organisation it often kept at the margins.

A century later, the memory of that moment still resonates. As part of the centenary celebrations - 100 Years of RSS - Prime Minister Narendra Modi is set to unveil a commemorative postal stamp depicting Sangh swayamsevaks marching in the 1963 Republic

Day Parade. This symbolic act is more than just nostalgia; it affirms how the Sangh's disciplined patriotism, once reluctantly acknowledged, is now celebrated as integral to Bharat's national story.

1965: Pakistan's Aggression

RSS Relief Efforts

When Pakistan launched "Operation Gibraltar" in 1965, sending infiltrators into Kashmir, the Indian Army responded with courage. The Sangh again mobilised swayamsevaks in Punjab, Delhi, and other regions for relief work, evacuations, and support to soldiers' families.

Guruji on Pakistan

Golwalkar interpreted Pakistan's hostility in civilisational terms. In Bunch of Thoughts he observed:

"Pakistan was born of the mentality opposed to Bharat's culture and unity. That mentality of aggression and hatred is not extinguished by partition. It continues to express itself in attacks across our borders."

He further noted that appeasement had encouraged aggression, "The rulers of Pakistan have no faith in peaceful coexistence. Theirs is the logic of the sword. Unless we stand united and strong, we invite repeated assaults."

For Guruji, Pakistan was not just a neighbour with territorial disputes but the product of a mindset shaped by the Two-Nation Theory, inherently opposed to Bharat's civilisational unity.

1971: Liberation of Bangladesh

Refugee Relief

By 1971, Pakistan's repression in East Bengal had created a humanitarian disaster, forcing millions into Bharat. The RSS, now under the emerging leadership of Balasaheb Deoras (who formally became the third Sarsanghchalak in 1973), played a critical role in refugee relief. Camps run by swayamsevaks in West Bengal, Assam, and Tripura provided food, shelter, and medical aid to lakhs of displaced families.

Deoras's Reflections

Deoras hailed the liberation of Bangladesh as historic justice, "Pakistan was created by breaking Bharat. Now Pakistan itself has broken. This is history's justice." (Speech, 1972)

At the same time, he warned against complacency, "Even after the victory, we must not lose sight of the fact that the mentality that created Pakistan still exists on our borders and within."

For Deoras, the 1971 war was not just a military triumph but a reminder that vigilance must continue until the deeper mindset of separatism and hatred is defeated.

The Sangh's Enduring Lessons

From these three wars, the Sangh distilled lessons that remain relevant:

¦ Unity is Security - Hedgewar and Guruji insisted that a united society is the best defence. A fragmented Bharat invites aggression; a united Bharat deters it.

. Civilisational Clarity - China was seen as expansionist by nature, intensified by Communism; Pakistan as the embodiment of the divisive Two-Nation mindset. Both required realism, not illusions.

Service as Patriotism - Whether 1962, 1965, or 1971, swayamsevaks proved that service at home is as much national defence as the soldier's duty at the front.

¦ Strength before Diplomacy - Panchsheel and "Hindi-Chini Bhai-Bhai" collapsed under the weight of aggression. For the Sangh, diplomacy without strength is empty.

¦ Dharma as Compass - Even in war, the Sangh's outlook was guided by Dharma: justice, duty, and civilisation.

not conquest or hatred.

From Reluctant Recognition to National Honour

The wars of 1962, 1965, and 1971 tested Bharat's resilience and revealed the Sangh's core convictions. Golwalkar's words about China being "expansionist in its blood" and Pakistan embodying a "mentality opposed to

Bharat's culture" were not mere polemics but civilisational diagnoses. Deoras's reflection that Pakistan's break-up was "history's justice" showed how the Sangh read geopolitics as history's unfolding of Dharma.

In all three wars, the swayamsevaks' discipline and relief work won national recognition. Most famously, after the 1962 conflict, Pandit Nehru - despite his hostility to the Sangh - was compelled to acknowledge their patriotism and allow them to march in the 1963 Republic Day Parade. What began as reluctant recognition has, in a hundred years, blossomed into open

honour.

As part of the Sangh's centenary, Prime Minister Narendra Modi will unveil a postal stamp showing swayamsevaks marching in that very parade of 1963. This gesture is more than symbolic; it marks how the RSS, once seen from the margins, is today celebrated as central to Bharat's national life. It tells the story of a movement whose strength lay not in political office but in discipline, service, and unwavering faith in Dharma.

As the Sangh enters its hundredth year, its wartime lessons remain relevant: unity is strength, clarity is protection, and service is patriotism. From Nehru's reluctant bow in 1963 to Modi's proud salute in 2025, the journey of the RSS is the journey of Bharat itself - from hesitation to self-confidence, from fragmentation to unity, from silence to civilisational assertion.

India upgrades ties with Afghanistan's----

friendly ties, but New Delhi does not recognise the Taliban government.

India and the Taliban are now recalibrating their ties because of souring relations with their neighbour Pakistan as well as New Delhi's concerns about major power rival China making inroads in Afghanistan, said Harsh Pant, foreign policy head at India's Observer Research Foundation think tank.

"Engagement does not mean endorsement. There are many things that India is uncomfortable about (under Taliban rule) - minority rights, gender rights, and the human rights landscape in Afghanistan," he said.

"But there is a pragmatism inherent in India's engagement with the Taliban ... And this visit is, in some ways, continuing that tradition. It certainly can be considered the beginning of a new phase in India-Afghanistan relations under the Taliban government, which have been one-directional so far."

Muttaqi's visit aimed to develop ties with New Delhi and highlighted Taliban efforts to expand engagement with regional powers in a quest for economic relations and eventual diplomatic recognition, analysts said.

Western diplomats have said the Taliban administration's path to recognition is being stalled by its curbs on women.

AFGHANISTAN WON'T BE SPRINGBOARD FOR TERRORISM, FOREIGN MINISTER SAYS

In his opening remarks on Friday, Muttaqi referred to ongoing counter-terrorism efforts and said the Taliban administration would not allow anyone to use Afghanistan's territory for targeting other nations.

"We hope that Afghanistan and India, on an official level and in different areas, increase their engagement," he said.

In his remarks about Friday's deal, Jaishankar said India was "fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan.

"Closer cooperation between us contributes to your national development, as well as regional stability and resilience," he said, adding that India's "technical mission" in Kabul was being upgraded to an embassy.

Jaishankar did not mention a timeline for the change.

India's Economic Outlook

-Dr. Rumki Majumdar
-Debdatta Ghatak

After weathering a year of global headwinds, from elevated interest rates to geopolitical tensions, India's macroeconomic fundamentals have shown remarkable resilience. The economy grew 7.4% year over year1 in the final quarter of fiscal year 2024 to 20252—with 6.5% growth for the whole year—setting the stage for a more confident outlook for fiscal year 2025 to 2026.3

Entering the new fiscal, India's economic outlook is buoyed by three key engines: a resilient consumer base, a broadening investment landscape, and a digitally skilled, dynamic workforce. Urban spending is rising, private capital expenditures are showing green shoots, and India's tech-adaptive talent is driving innovation and showcasing its global capabilities.

The August edition of India economic outlook explores these key drivers behind India's resilient growth, and how it has performed compared to its peer nations. This edition also briefly touches upon the evolving dynamics of India's trade positioning in the global economic landscape. Amid an evolving and uncertain trade landscape, India is laying the groundwork for deeper market access, stronger intellectual property protections, and expanded investment corridors. The pace at which India is working on these agreements suggests that these are not just trade instruments, but strategic levers that will amplify domestic growth drivers and open new growth frontiers for the country.

Accounting for the resilience in economic fundamentals, easing inflation levels, and bold policy stimuli aligned for expansion this year, Deloitte expects a baseline forecast of 6.4% to 6.7% GDP growth this fiscal year and stronger growth in the next fiscal year.

Resilience in economic fundamentals in the last quarter pushed growth for fiscal year 2024 to 2025

India's GDP growth numbers for the last quarter of fiscal 2024 to 2025 came as a welcome surprise, with the economy growing at a brisk 7.4% year on year. Growth for the full fiscal year came in at 6.5%, driven by strong private consumption expenditure and investments, indicating domestic demand might be more resilient than expected, supported by easing inflation and favorable conditions in rural economies.

Private final consumption expenditure grew 6% in the last quarter of fiscal year 2024 to 2025. Although consumption spending growth slowed this quarter, annual growth was 7.2%, which was well ahead of overall GDP growth.

What came as a relief is that, after years of being led primarily by the government, green shoots were visible in private investment, suggesting broader participation in capex formation. Gross fixed capital formation rose by a strong 9.4% in the fourth quarter, up from an average of 6.2% in the last three quarters. However, full-year gross fixed capital formation growth was more modest at 6.7%; the fourth-quarter acceleration may suggest that private capex may have turned the corner, as consumption spending showed signs of improvement.

The impact of global risks and trade headwinds led to a moderation in exports to 3.9% in the fourth quarter compared with an average 7.4% seen in the past three quarters. Nonetheless, exports for the full fiscal year grew at 6.3%, an improvement compared with the 2.2% seen in fiscal year 2023 to 2024. Goods exports were affected more than services exports, and the latter helped India to reduce its annual current account balance to –0.6% of GDP—the lowest since fiscal 2016 to 2017 (except during the pandemic when the balance moved to a surplus). (-Contd. in next issue)

4 Key Obstacles to India Joining UN Security Council With Veto Power

-Dhananjay Tripathi

Indian politicians have argued for decades that the nation deserves to be a member of the United Nations Security Council (UNSC).

An aspirational superpower, India believes that it has been unfairly denied a seat at the high table.

Several visiting foreign political dignitaries and international coalitions that have pushed for UNSC reforms have also voiced support for India's candidacy for permanent membership of the Security Council.

However, despite persistent lobbying by India, experts are not hopeful of change in the near future.

There are four key challenges India must overcome before it secures veto power in the United Nations.

CHINA'S OPPOSITION

Among the five permanent security council members all except China - the US, the UK, France, and Russia - have categorically supported India's candidature in the past.

As a close competitor of India in regional and international politics, China - the only Asian country with a security council seat - is unwilling to endorse New Delhi's position.

This adds to its power and international prestige and China is unlikely to want to share this space with India. What's more, particularly amid an ongoing border dispute with India, China will resist any attempt by any of the four members to change the composition of the UNSC.

China is also uncomfortable with Japan, a close US ally that, like India, is a strong contender for a permanent seat.

China has unofficially dropped hints that it may back India, provided New Delhi doesn't endorse Japan's bid. China knows that New Delhi will not break the unity of the G-4 (comprising Brazil, Germany, India, and Japan, are four countries which support each other's bids for permanent seats on the security council) and thus, considers it is a safe bet to pit India against Japan.

DISAGREEMENT ON MEMBERSHIP WITHOUT VETO POWER

Some parties have raised the prospect of India gaining UNSC membership without veto power.

Groups including Uniting for Consensus (UfC) - a powerful coalition led by Italy, with other members including Canada, Mexico, Spain, Pakistan, South Korea and Turkey - have advocated reinforcing the working of the General Assembly and increasing the number of non-permanent members.

Its argument is that the addition of non-permanent members will make the UN more accountable and representative by accommodating relevant regional voices in the decision-making process. In doing so, the group argues, this solution would mean there are more than a few select chief custodians of the international system.

But there are questions about what happens if India gets a high seat without veto power. Could this be considered a piecemeal approach towards achieving the larger objective?

Despite some parties saying they prefer this kind of arrangement, New Delhi is not

comfortable with this proposition. India's position is that all new permanent members to the security council must possess a veto. Thus, it is unlikely this outcome will unfold.

WESTERN CONCERNS THAT INDIA MAY NOT ALIGN WITH US PRIORITIES

The US has, in principle, endorsed India gaining a permanent seat on the security council. But not everyone believes US policymakers will actually support such a reform in practice.

Indeed, in the past, P-5 countries have displayed "a habit of being non-commital" when it comes to actual decision-making on veto powers. As former US Under Secretary of State for Political Affairs Nicholas Burns said in 2008: "We want to preserve the veto, and we do not want to extend a veto to new permanent members."

Prominent US-based South Asian expert Ashley Tellis recently penned a piece in Foreign Affairs magazine arguing that the US cannot be sure of India's support on significant strategic matters. Ashley later defended this position in an interview, saying "the current war in Ukraine is a good example... India defines its interest in ways that are not always identical to our own".

It is true that India has not always voted with the West in the UN and has maintained an independent position on several critical subjects (e.g., India abstaining on the Russian invasion of Ukraine). Due to this, many think India is a fence-sitter and see it as an unreliable partner.

The West, particularly after the Russian-Ukraine war, is more watchful of new geopolitical reality. The understanding that Russia may fail to secure any support in the world for its war has changed.

Despite developing closer strategic ties with the West, India remained uncommitted on supporting sanctions on Russia. While China's response was anticipated, for the West, foot dragging by New Delhi in criticising Russia was no less than a shock.

In these changed circumstances, it is difficult to imagine that the West, particularly the US, will go ahead with a reformed security council where India has veto power.

THE REGIONAL CONUNDRUM

India also faces formidable challenges to its leadership emanating from its own region. India influences the region, but not in absolute terms. Indeed, as instability in the region has increased, so too have New Delhi's troubles.

South Asia has become a battleground of India-China competition.

And while the India-Pakistan rivalry captures most attention, there are major India-related issues that agitate people in Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives and even in Bhutan.

With its recent change of government, Bangladeshis no longer on the same page. Queries over India's regional leadership raises questions over its claims to be a global power.

NEXT STEP FOR INDIA

There are convincing arguments that the UN is in desperate need of reform, particularly the Security Council. Expanding the Security Council's membership to include developing countries like India would benefit the UN and the international community.

However, New Delhi must make more concerted efforts to address criticisms to further legitimise its demand for permanent membership.

India's geographical, political, and social influence in South Asia cannot be ignored. Recent criticism around its increasing political intolerance - which is directly linked to the state of democracy in India - must be addressed and resolved.

India's failure to improve its ranking in the Human Development Index, the issue of economic inequality, and its lack of world-class infrastructure all contribute to the nation's global image. Therefore, there are structural and more prominent geopolitical factors that overshadow India's chances to acquire security council permanent membership.

Additionally, India needs better engagement with the region and much more internal work to strengthen its claim further.

गतिविधियां (Social Activities)

– जे. बी. एस. चौहान

कांशी प्रांत (उ.प्र)–'डॉ कृष्णानंद पांडेय को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद (काशी प्रांत) का संगठन मंत्री बनाया गया' आज दिनांक 28 सितंबर को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद काशी प्रांत की एक बैठक काशी (चंदौली) में आहूत की गई तथा बैठक के दौरान डॉक्टर कृष्णानंद पांडे को संगठन मंत्री सर्वसम्मति से चुना गया। इस अवसर पर काशी प्रांत अध्यक्ष के द्वारा उन्हें परिषद की टोपी पहना कर सम्मानित किया गया स इस बैठक में काशी प्रांत के एजीएम की तिथि 2 नवंबर मैक्सवेल हॉस्पिटल काशी (चंदौली) में तय किया गया। इस बैठक में श्रीमान रेवती रमण तिवारी अध्यक्ष काशी प्रांत, श्री अयोध्या प्रसाद वर्मा उपाध्यक्ष काशी प्राप्त श्री सत्यनारायण त्रिपाठी कोषाध्यक्ष काशी प्रांत श्री सुदीप कुमार मिश्र महासचिव काशी प्रांत, श्री लक्ष्मी नारायण सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर आदि पूर्व सैनिक उपस्थित रहे।

मेरठ प्रांत (उ.प्र.)–अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद मेरठ प्रांत का वार्षिक सम्मेलन दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को विराट फार्म हाउस बुलंदशहर में जिला अध्यक्ष हरिप्रकाश सिंह की अगवाई में संपन्न हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष कर्नल लखन सिंह तथा प्रांत अध्यक्ष कर्नल नवरत्न सिंह रहे तथा संचालन प्रांत सचिव बलविंदर सिंह द्वारा किया गया इस सम्मेलन में विभिन्न जिलों से आए हुए पदाधिकारी और सदस्य तथा मातृशक्ति ने हिस्सा लिया इस सम्मेलन में जिलेवार विषयों पर चर्चा हुई तथा मुख्य अतिथि द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए इसी के साथ रामसेवक शर्मा को प्रांत महासचिव पद दायित्व दिया गया।

रीवा (म.प्र.)–भारत–पाक 1965 के युद्ध में ग्राम पंचायत खड्डा, तहसील सिरमौर के मांटी का लाल सिपाही रामचरण शुक्ल ने भारत माता की रक्षा करते हुए व दुश्मन देश की सेना से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान 20 सितंबर 1965 को दे दिया था। उनके 60 वां बलिदान दिवस का कार्यक्रम ग्राम पंचायत खड्डा मे निर्मित स्मारक पर गरिमा पूर्वक दिनांक 20 सितंबर 2025 को मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी रहे थे, अध्यक्षता अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के राष्ट्रीय सचिव सार्जेंट रमेश पाण्डेय ने किया। विशिष्ट अतिथि के रुप में पूर्व भाजपा विधायक श्री के पी त्रिपाठी जी के पिता श्री कमलापति त्रिपाठी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रीवा लेफ्टीनेंट कर्नल पी गंगा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सीधी ग्रुप कैप्टन एस श्रीवास्तव, परिषद के जिला कार्यकारी अध्यक्ष कैप्टन अनिल कुमार सिंह, ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती चम्पा शुक्ला और वीर नारी श्रीमती सिया दुलारी जी रहे थे।

गुवाहाटी (असम)–बदलते वैश्विक परिदृश्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा विषय पर एक संवाद का आयोजन एबीपीएसएसपी असम प्रांत और द ग्लोबल यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश द्वारा 7 अक्टूबर 2025 को सैनिक भवन, गुवाहाटी में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल पीके भराली वीएसएम थे। मुख्य वक्ता मा. उल्हास कुलकर्णी जी, सदस्य, कार्यकारी समिति, आरएसएस थे। अन्य वक्ताओं में डॉ. मृदुल हजारिका, पूर्व कुलपति, गुवाहाटी विश्वविद्यालय और श्रीमंत शंकर देव विश्वविद्यालय तथा ब्रिगेडियर पोलास चौधरी, निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड असम शामिल थे। कर्नल रंजीत तालुकदार, अध्यक्ष, एबीपीएसएसपी असम प्रांत ने स्वागत भाषण दिया और कर्नल जगदीश लाल, महासचिव, एबीपीएसएसपी असम ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

अवध प्रांत (उ.प्र.)–अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अवध प्रांत का वार्षिक सम्मेलन दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को सर्किट हाउस अयोध्या में श्री प्रकाश पाठक, अध्यक्ष अयोध्या इकाई की अगुवाई में सम्पन्न हुआ। अवध प्रांत के सात जिलों के प्रतिनिधिमंडल और मातृ शक्ति समेत कुल 125 पूर्व सैनिकों ने भाग

लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश सहित अनेक विषयों और जिलेवार वृत्त पर चर्चा हुई। राष्ट्रगान के बाद सम्मेलन पूर्ण हुआ। भोजनावकाश के बाद समापन किया गया।

बस्ती (उ.प्र.)– बस्ती (उ.प्र.) में स्थित स्वामी विवेकानंद फारमेसी महाविद्यालय में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, गोरक्ष प्रांत का वार्षिक महाअधिवेशन बड़े ही हर्ष उल्लास व धूमधाम से मनाया गया। जिसके दौरान मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के प्रांतीय संरक्षक ब्रिगेडियर गोविंद जी मिश्र, वीएसएम, विशिष्ट अतिथी के रूप में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ बस्ती के विभाग प्रचारक श्रीमान रिऋ जी, प्रांतीय अध्यक्ष कर्नल, एस पी सिंह, महासचिव कर्नल डा. रामाश्रय मिश्र, सचिव कैप्टन भाष्कर पांडे, कोषाध्य सु. मेजर, नित्यानंद तिवारी संस्था के प्रांतीय संगठन मंत्री डा. शशि भूषण शर्मा व सैन्य मातृ शक्ती की प्रांतीय संरक्षिका श्रीमती प्रिती त्रिपाठी जी पत्नी ब्रिगेडियर जितेंद्र त्रिपाठी, प्रातीय अध्यक्षा श्रीमती बिमला शर्मा जी सहित गोरखपुर, बस्ती व आजमगढ मंडल के अंतर्गत आने वाले दसों जिलों से संस्था के जिला अध्यक्ष, सैन्य मातृ शक्ति व भारी संख्या में पूर्व सैनिक व बीरनारी उपस्थित थे।

बंगलोर–राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक परम पूज्य मोहन जी भागवत जी के सानिध्य में और सर कार्यवाहक माननीय दत्तात्रेय होसवोले जी, राष्ट्रीय सेवीका समिति प्रमुख संचालिका वी शांताकुमारी जी और महिला समन्वय प्रमुख मीनाक्षी ताई जी की गरिमा पूर्ण उपस्थित मे दो दिवसीय महिला समन्वय अखिल भारतीय बैठक 12–13 अक्टूबर को जनसेवा विद्या केन्द्र, बंगलोर मे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सैन्य मातृशक्ति की प्रमुख संयोजिका श्रीमती माया कोल जी, सह संयोजिका कैप्टन (नि) मीरा दवे जी और राष्ट्रीय मंत्री वेटरन अशोक कुमार चावड़ा उपस्थित रहे थे, अति महत्वपूर्ण विषयों एवं योजनाओं पर जानकारी, मार्गदर्शन प्राप्त करनेका अवसर मीला।

जम्मू काश्मीर–आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों ने परगवाल में युद्ध विधवाओं, विधवाओं और निम्न आय वर्ग के अन्य परिवारों से बातचीत की और उनका दुख साझा किया तथा नुकसान का आकलन किया।

दिल्ली प्रदेश–अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद दिल्ली की उत्तरी जिला इकाई एवं साईं मोबीडेन्ट डेन्टल सैन्टर, रोहिणी, दिल्ली के संयुक्त रूप से बाबा नन्हे नाथ राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय खेड़ा कलॉ, दिल्ली में एक तीन दिवसीय 23 सितम्बर से 25 सितम्बर 2025 तक फ्री कांप्रीहेन्सिव डिजिटल डेन्टल चेकअप कैम्प लगाया गया जिसमें 350 छात्राएं व स्कूल स्टाफ लाभान्वित हुए। यह चेकअप कैम्प अति कुशल 4 डाक्टर्स व 2 सहायकों की सहायता से वर्ल्ड की लेटेस्ट मेडिकल उपकरणों से लैस मोबाईल वैन में किया गया। कैम्प की शुरुआत पूर्व सैनिकों, डाक्टर्स टीम, व स्कूल स्टाफ को स्कूली छात्राओं द्वारा चन्दन टीका लगाने व दीप प्रज्जवलन करके की गई ।सरस्वती वन्दना और राष्ट्र गान 'जन गण मन' के बाद प्रिंसिपल महोदया श्रीमती दीपिका जी द्वारा पूर्व सैनिकों व डाक्टर्स टीम को पौधा–गमले देकर सम्मानित किया गया। कैम्प के प्रथम दिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 110 छात्रों का चेकअप किया गया, दूसरे दिन 105 और तीसरे दिन 135 छात्राओं का (कुल 350 छात्राएं) चेकअप किया गया व प्रिंसिपल महोदया और स्कूल स्टाफ का भी डेन्टल चेकअप किया गया। स्कूल वातावारण बहुत ही अनुशासित था और सभी छात्राओं व शिक्षक गणों का विशेषकर मैडम गायत्री शौकीन, हैल्थ एंड हाईजीन इंचार्ज मैडम मृणाली गौरव एवं एस्टेट मैनेजर श्री वेदपाल राणा जी का सहयोग अति सराहनीय रहा। कैम्प के दौरान कैम्प की समस्त टीम को विद्यालय की तरफ से स्वादिष्ट जलपान व लंच की उत्तम व्यवस्था अति सराहनीय रही। डाक्टर्स की समस्त टीम व पूर्व सैनिकों की टीम ने अपने अनुशासित कुशल व्यवहार, सेवा व योगदान से विद्यालय के सभी शिक्षक गण , स्टाफ का दिल जीत लिया। डॉ . अरोड़ा जी ने कहा कि सैनिक परिषद के माध्यम से आने वालों को परामर्श फीस में 25 फीसदी छूट मिलेगी।